students) and people of Indian origin live in Australia today. The older, more established Indian community in Australia consists largely of skilled professionals, such as doctors, accountants, engineers and academics. It has traditionally been seen as a model migrant community and lauded for its contribution to the Australian economy, having settled and integrated well, and highly regarded for their industry and skills. The Indian community through its culture and values is contributing in making Australia the vibrant multi-cultural society that it is today. They are a vital bond between our two countries.

Let there be no doubt that we take the incidents of assault on our students very seriously indeed. I would like to assure you that the Australian authorities have been fully apprised of the gravity of the situation. As a result, both at the state as well as the federal level, they have taken several measures as outlined above, to improve security and surveillance; it can be honestly said that they are making efforts to meet our concerns. However, as can be seen, the issue consists of several complex factors, all of which are interlinked and need to be dealt with in a concerted and coordinated manner.

I assure the House that we will continue to monitor the situation closely and work closely with the Australian authorities to deal with the issues concerned and improve the safety and security of our students in Australia. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The clarifications on this statement will be taken up some other day. Now, Shri Ravi Shankar Prasad.

SHORT DURATION DISCUSSION - *Contd.*

Situation arising out of continued rise in prices of essential commodities in the country

श्री रवि शंकर प्रसाद : उपसभापति महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। मैं सुबह से महंगाई पर इस बहस को सुन रहा हूं। विशेष रूप से मैंने कांग्रेस के सम्मानीय सदस्य और एनसीपी के सदस्य को जब सुना तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। महोदय, जब से यूपीए सत्ता में आई है, तब से हम शायद यह सातवीं बहस महंगाई पर कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि पिछली बार शरद पवार साहब ने इस बहस का उत्तर देते हुए इसी हाउस में कहा था कि मैं वादा करता हूं कि जनवरी से आम आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, कीमतें नीचे होंगी। आज फरवरी समाप्त हो रही है और आम आदमी की कराहट, परेशानी और आंसू और अधिक बढ़ गए हैं। मुझे इस बात की पीड़ा और जरूर है कि जिस हल्के तरीके से सत्ता पक्ष के लोग इस पूरे रोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर क्या कहा जाए? कमलनाथ जी मंत्री हैं, उन्होंने कहीं पर कह दिया कि लोगों ने आजकल अधिक खाना शुरू कर दिया है, खुराक बढ़ गई है इसलिए महंगाई बढ़ गई है। मेरे पास शीला दीक्षित जी का वक्तव्य है, वे लोकप्रिय मुख्य मंत्री हैं। उन्होंने कह दिया कि लोगों की कमाई बढ़ गई है, इसलिए महंगाई बढ़ गई है। एनसीपी की एक पत्रिका में कहा गया, चीनी न खाओ, डायबिटीज़ हो जाएगी तो मुझे एक फिल्म "चीनी कम" की याद आ गई। पता नहीं यह सब क्या कहा जा रहा है। It is a cruel and ugly joke on the plight of the common people. यह मैं कहना चाहता हूं, क्रूर मजाक है। यह जख्म पर नमक रगड़ने के समान है। जब भी यह बात करते हैं तो लगता है कि सरकार की उदासीनता पराकाष्ठा पर है।

[उपसभाध्यक्ष (**प्रो. पी.जे. कुरियन**) पीठासीन हुए]

मैं देख रहा था, शरद पवार जी यहां थे, अब चले गए हैं। एक दिन कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जो इस हाउस के सदस्य हैं, सम्मानीय जनार्दन द्विवेदी साहब, उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री का काम सिर्फ समस्या को बताना नहीं

है, उसका रास्ता भी दिखाना है। अब एनसीपी के विद्वान सदस्य पता नहीं कहां से सूची लेकर चले आए कि कीमतें घट रही हैं। मुझे एक शेर याद आ गया:

तू इधर उधर की बातें न कर, सीधा बता कि कारवां आखिर क्यों लूटा है?

आप क्यों हमें अहमदनगर ले जा रहे हैं, आप दिल्ली चलिए, चांदनी चौक चलिए, बगल में रेलवे भवन के सामने उस गरीब कैंटीन में चलिए, फरीदाबाद चलिए, हमारे बिहार में चलिए, जाबिर हुसेन साहब के साथ जाइए, जिसके साथ भी जाइए, आपको हर जगह गरीब आदमी कराहता हुआ मिलेगा और कीमतें बढ़ती हुई मिलेंगी। कम से कम इस तरह की गलतबयानी आप हाउस के अंदर मत करिए कि कीमतें गिरी हैं।

श्री गोविंदराव आदिक : आप मेरे साथ मेरे गांव में चलिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद : आपके गांव? वह आपके प्रभाव का क्षेत्र है।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): No, no. ...*(Interruptions)*... You please address the Chair.

श्री रवि शंकर प्रसाद : उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे एक और बात की पीड़ा है। कभी कहा जाता है कि प्राकृतिक विपदा आ गई, अकाल आ गया। वाजपेयी जी की सरकार 6 साल तक थी। 2001-02 में 14 राज्यों में सबसे बड़ा अकाल पड़ा था। फिर भी किसानों को अच्छी कीमत दी गई, उन्होंने फसल उगायी, लोग राशन कार्ड भूल गए थे और कीमतें स्थिर थीं। 6 साल तक जनता खुश थी - यह हमने दिखाया है। आज ऐसा क्या हो गया है that the economy of surplus, which we left, has become the economy of scarcity. उपसभाध्यक्ष जी जब महंगाई और कीमत की बात आती है तो दो चीजें सामने आती हैं - डिमांड और सप्लाई, अगर डिमांड, सप्लाई में तीसरा एंगिल जुड़ जाता है - सत्ता की राजनीति, तो और विकराल रूप हो जाता है। फूड इंफ्लेशन की, महंगाई की 20 परसेंट रेट है। जब कांग्रेस की ओर से शरद पवार जी को कहा गया कि आपको संभालना है, तो उन्होंने कहा कि यह पूरे केबिनेट की जिम्मेदारी है। वैसे शरद पवार जी थ्री-इन-वन हैं। कृषि मंत्री हैं तो देखना है कि फसल पैदा हो, खाद्य मंत्री हैं तो देखना है कि खाद्य उपलब्ध हो और कंज्यूमर्स एफेयर्स के मंत्री हैं तो यह भी देखना है कि उपभोक्ताओं को सस्ता सामान मिल सके। लेकिन ऐसे कृषि मंत्री हैं कि मुंह खोलते हैं और गरीब जनता रोती है, बीच वाले मुस्कराते हैं। यह पता नहीं क्या हो रहा है? जब कांग्रेस से हमला हुआ, तो शरद पवार जी देश के वरिष्ठ नेता हैं, हम सम्मान करते हैं, वे चार बार मुख्य मंत्री रहे हैं, दो बार मंत्री रहे हैं। अब मुम्बई में एक जगह मिलने के लिए चले गए। क्यों मिलने गए? तो सुनने में आया कि क्रिकेट के मैच में होने वाली कठिनाई को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ बात समझ में नहीं आई कि जनता महंगाई से परेशान है और कोई क्रिकेट खिलाने के लिए परेशान है जो मंत्री है, तो शायद दूसरे दिन अखबारों में कुछ टिप्पणियां आ गईं, वह संकेत दे रहे थे कि हम दूसरे पिच पर भी क्रिकेट खेलने का हौसला रखते हैं। उधर से आवाज आ गई कि पूरी केबिनेट जिम्मेदार है। जब दूसरी बार कहा गया कि चीनी मत खाओ डॉयबिटीज हो जाएगा तो फिर जब दबाव पड़ा अंदर के घात-प्रतिघात, तो उपसभाध्यक्ष जी, मुझे जरा संगीत का शौक है, शास्त्रीय संगीत का समय होता है, सुबह में भैरवी बजती है, शाम में यमन

कल्याण बजता है और एक राग दरबारी भी होता है जिसको मियां तानसेन ने बनाया था। सुन्दर राग है। लेकिन राग दरबारी जब बेसुरा लगता है तो दरबार का सुर भी बिगड़ जाता है। जब दबाव पड़ने लगा तो एकाएक एन.सी.पी. के एक नेता ने कहा कि the Prime Minister must be elected. अब हमें समझ में नहीं आया कि महंगाई की उठा पठक में the Prime Minister should be elected and not selected or nominated. यह बात कहां से आ गई। उपसभाध्यक्ष जी, यह बात मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि महंगाई के नाम पर राजनीति हो रही है कॉएलेशन पौलिटिक्स में, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात हो रही है, जिम्मेदारी से भागने की बात हो रही है और जनता परेशान है। महंगाई का यह सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि फूड इकॉनोमी को इस सरकार ने मिस-मैनेज किया है, यह हमारा स्पष्ट आरोप है। मैं आज उसको प्रूव करूंगा, आंकड़ों से प्रूव करूंगा। फिर एक बात आई कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। जब मैं यह तर्क सुनता हूं तो मुझे हंसी आती है। दिल्ली में किस की सरकार है? कांग्रेस पार्टी की सरकार है? शीला दीक्षित लोकप्रिय मुख्य मंत्री हैं। जाइए दिल्ली की सड़कों पर, महंगाई का आलम देखिए। मुम्बई में किस की सरकार है? आपकी सरकार है, तीसरी बार आप वहां जीतकर आए हैं। चलिए मुम्बई की सड़कों पर। राजस्थान में भी आप जीतकर आए हैं। उपसभाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार इतनी हताश है कि इसके पास कोई समाधान नहीं है। They are talking the language of desperation. इसके लिए मैं कल के टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली के बारे में कहना चाह रहा हूं। यह देखिए 20 तारीख में आलू होलसेल मार्केट से तीन रुपए में निकलता है और दिल्ली के बाजारों में मिलता है 12 रुपए में। यह जो प्याज है, वह निकलता है 11 रुपए में और मिलता है 25-30 रुपए में। वही हाल गेहूं का भी है। टमाटर 6 रुपए में निकलता है और मिलता है 15 से 22 रुपए में। पूछिए तो कहते हैं कि बिचौलियों को हम लोग नहीं रोक पा रहे हैं। किसने मना किया आपको रोकने से? उपसभाध्यक्ष जी, मैं आज दो-तीन आंकड़े बड़ी ईमानदारी से प्रस्तुत करना चाहता हूं। कहा गया कि हमने किसानों को बहुत कुछ किया है। ठीक है इस देश के किसानों ने पैदावार बढ़ाई है। मंत्री जी, यह आपके आंकड़े हैं, इनको सुन लीजिए। कमी बिल्कुल नहीं है। 2008-2009 में किसानों ने 805 लाख टन गेहूं पैदा किया है। आप क्लेम करते हैं कि it is a record production. चावल 991 लाख टन आपने प्रोड्यूज किया है और आपने उस गरीब किसान को कितना दिया है। कहते हैं कि बहुत दिया है। चीनी 50 रुपए किलो चल रही है, उसका हिस्सा 14 रुपए में आता है। बाकी यह 26 रुपए कहां जाता है। चावल 30-32 रुपए किलो चल रहा है, किसान को 10 रुपए मिलता है। किसान की आत्महत्या जारी है। अभी वृंदा जी और बाकी सदस्यों ने फर्टिलाइजर पर सब्सिडी हटाने की, महंगाई की बात कही, हम सभी उनके साथ हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसानों के दर्द को मिटाने का जो आप दावा कर रहे हैं, आप उनको दे क्या रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल है और दूसरा सवाल और इम्पोर्टैंट है कि जब किसान की फसल तैयार होती है, तभी आपकी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट नीति में क्यों बदलाव होता है? यह बड़ा सवाल है। आप कहते हैं कि हमारे पास पूरा सामान है, फिर भी आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, फिर भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट पर सब्सिडी दे रहे हैं। अब मैं चीनी पर आता हूं। क्योंकि मैंने कहानी डायबिटीज से शुरू की थी और "चीनी कम" सिनेमा से शुरू की थी, मैं अब चीनी पर ही आता हूं। चीनी का देश में कितना भंडार है, मंत्री जी, मैंने पिछले सत्र में एक सवाल किया था, Unstarred Question No. 191 और इसका

उत्तर मेरे पास है। It is part of parliamentary records. चीनी अक्टूबर, 2008 में 25 रुपए थी, अक्टूबर 2009 में 45 रुपए हो गई और आज 50 रुपए के आसपास है। देखिए, 2008 में, आपके इस उत्तर से है, जो फाइनेंस की स्टैंण्डिंग कमेटी, सिक्स्थ रिपोर्ट में भी एग्जामिन किया है, जिसका जिक्र माननीय वृंदा जी ने किया था, वह रिपोर्ट मेरे पास है। आपका ओपनिंग बैलेंस 100 लाख टन का था, 105 लाख टन का था। आपकी फसल 146.08 लाख टन पैदा हुई और आपने 10.08 लाख टन इम्पोर्ट किया। Therefore, the total availability of sugar last year was 257.6 lakh tonnes. और भारत की जो कंजप्शन है, जो लोग टोटल लेते हैं, वह 220 लाख टन है। यानी आपके पास 27 लाख टन का सरप्लस था। फिर भी कहते हैं कि चीनी कम है। इसका क्या मतलब है? यह गड़बड़ी क्यों हो रही है? या तो आपके आंकड़े सही नहीं हैं, या आप पार्लियामेंट में मिसलीड कर रहे हैं, या आपके ऑफिसर स्टैंण्डिंग कमेटी को गलतबयानी कर रहे हैं। अगर चीनी का सरप्लस है तो चीनी महंगी क्यों है, यह बात समझ में नहीं आती। उपसभाध्यक्ष जी, मैंने इसको एग्जामिन करने की कोशिश की। शुगर फैक्ट्री का जो एक्स फैक्ट्री प्राइज है, 16.12.2009 को 3300 रुपए पर क्विंटल था। मात्र बाइस दिन बाद 7.1.2010 को यह बढ़कर 4300 रुपए पर क्विंटल हो गया। From Rs. 3300 to Rs. 4300, that is, rise of Rs. 1000 per quintal only in 22 days. आपके पास चीनी है, यह आपका दावा है, ये आपके आंकड़े हैं। मैंने सब डाउनलोड किया है। आपके पास चीनी है, चीनी कम नहीं है, सरप्लस भी है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि जनता परेशान है तो कहीं न कहीं बिचौलियों के साथ मिली-भगत है, हम यह आपसे बहुत ईमानदारी से और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं। Mr. Vice Chairman, Sir, it is my charge with full sense of responsibility that the UPA Government's policies are tailor-made for middlemen, speculators and not for the common man. That is the reason of this gross mismanagement of food economy. This is my charge, which I am saying with full sense of responsibility. अब मैं थोड़ा दाल पर आता हूं। दाल पर भी बहुत चर्चा हुई है। हमने 2008-09 में, मंत्री जी, फिर आपके आंकड़े हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, आपने 14.66 मिलियन टन दाल पैदा की और आपने 2.44 टन दाल इम्पोर्ट की यानी टोटल दाल 17.10 मिलियन टन थी। आपका दाल का कंजप्शन, देश का 17.51 मिलियन टन था। कमी कितनी थी, The shortfall was only 0.40 million tonnes. इसके बावजूद दाल के नाम पर सेंचुरी लग रही है। क्या मतलब है? दाल में कितना काला है? यह सब आपके आंकड़े हैं। मैं कह रहा हूं कि आदमी अनुभव से सीखता है। शरद पवार जी 2004-05 से मंत्री है। हमने सोचा कि जरा उन पहले के आंकड़े को भी देखा जाए। आदमी अनुभव से सीखता है, सुधरने की कोशिश करता है। आपकी सरकार आम आदमी की सरकार है। आज मैं पूरी जिम्मेदारी से एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि महंगाई तभी क्यों बढ़ती है, जब कांग्रेस सत्ता में आती है? इस सवाल का साफ-साफ जवाब दिया जाए। कहा गया कि हमारे प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हैं। हम भी मानते हैं।

वे नामी अर्थशास्त्री हैं। हमें यह बताया गया कि वे अपने अर्थशास्त्र के अनुभव का लाभ लेते हुए भारत को विकास के शास्त्रीय मार्ग पर ले जाएंगे। ये बातें हमने भी सुनीं। अब पिछले की बात को छोड़ दें, 2005 मई में जीते, तो कहा कि 100 दिन में महंगाई कम होगी। सारे मंत्री, 100 days, 100 days. वे 5 साल भूल गए। अब तो 9 महीने से अधिक हो गए। उपसभाध्यक्ष जी, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त आकृति भी 9 महीने में आकार लेकर अवतरित हो जाती है, लेकिन यह महंगाई तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। Why this gross mismagement of food economy under an economist Prime Minister is the question we are entitled to know and we seek explanation not only from Sharad Pawarji, but also from the Prime Minister? It is the collective responsibility. आपके अन्दर की जो लड़ाई है, उसके कारण आम आदमी परेशान नहीं हो सकता।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं दाल के बारे में एक कहानी और कह दूं। 2004-05 में कमी सिर्फ 3.02 मिलियन टन की थी, फिर भी इस रेट से दाल की कीमत नहीं बढ़ी, जबकि अभी पिछले साल यह 0.41 मिलियन टन है और दाल

सेंचुरी लगा रही है। 2004-05 में जब इनकी सरकार आई थी, तो 3.02 मिलियटन टन थी, फिर भी वह इतनी आगे नहीं भागी थी। गेहूं, चावल की बात मैंने कर दी। गेहूं ज्यादा है, चावल काफी हुआ है, किसान को आप अच्छा देने का वादा करते हैं, चीनी कम नहीं है, फिर भी महंगाई क्यों है? उपसभाध्यक्ष जी, दूध और सब्जी क्यों महंगी हो गई? इसके लिए कौन सा global factor जिम्मेदार है? ये गोभी, बैंगन, आलू और टमाटर क्या चीन से आते हैं या कोलंबिया से आते हैं या अर्जेंटीना से आते हैं? आप दिल्ली के बाहर निकलिए, हमारे किसान कितने अच्छे आलू पैदा करते हैं। जाबिर हुसैन साहब हमारे बिहार से आते हैं, हम लोग पटना से आगे बढ़ें, तो देखिए, आलू और बाकी चीजों की कितनी अच्छी खेती होती है। पूरे देश में किसान इतनी पैदावार करता है, फिर भी आलू महंगा है, टमाटर महंगा है, हर प्रकार की सब्जी महंगी है। दूध के बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। दूध से एक 'केसीन' नाम का तत्व बनता है, जिसकी विदेश में बहुत मांग होती है। उसे पिज्जा पर लगाया जाता है और उसका उपयोग होता है। 70 किलो दूध से एक किलो 'केसीन' बनता है। इस 'केसीन' को रोकने की बात चल रही थी। यह नहीं रुक पा रहा है। अब मैंने मीडिया में सुना है कि बारामती में इसकी एक बड़ी फैक्टरी है। यह किसकी फैक्टरी है, हमें पता नहीं है, लेकिन बारामती की एक बड़ी फैक्टरी बड़ा 'केसीन' बनाती है, दुनिया में नाम करती है। क्या कुछ छोटे-बड़े उद्योग के लिए आम जनता की कराहट को आगे बढ़ाया जाएगा? ये बड़े सवाल हैं।

अब कहा गया कि इसके लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। वृंदा जी ने भी एक सवाल किया, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। मंत्री जी साफ-साफ बताइए कि देश में procurement policy कौन तय करता है, export-import policy कौन तय करता है, foodgrains के movement की नीति को कौन तय करता है? यह आप तय करते हैं। Future trade, जिसके बारे में वृंदा जी ने बात की है, हमारे नेता अरुण जी ने बात की है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। वह तो बहुत बड़ा scam है ही। वह आप ही तय करते हैं। फिर भी जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों की है! आज मैंने बहुत आंकड़े रखे हैं। मैं एक आंकड़ा और रखना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि शरद पवार जी, kindly confirm करिए and Mr. Minister of State for Agriculture, I hope you are listening to me. Sir, he is not attentive at all. अब मैं क्या बोलूं? अब शशि थरूर जी को मैं कहां से ध्यान दिलाऊं, वे तो विदेश राज्य मंत्री हैं and I am not on Twitter at all. माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं जो बात कह रहा था, इस बात को आप नोट करें कि अभी जो मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें raids की बात हुई थी। जब डाटा पूछा गया कि इस देश में किन-किन प्रदेशों में raids हुई हैं, तो डाटा यह सामने आया कि UPA ruled State Governments में 17 प्रतिशत raids हुई हैं और बाकी maximum raids non-UPA State Governments में हुई हैं। आप तो अपनी सरकार को संभाल नहीं पा रहे हैं। हम यह नहीं कहते हैं कि सरकारों को काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी जो adhoc नीति है, उसका एक बिहार का उदाहरण सामने आया। शरद पवार जी ने कहा कि हम 20 लाख टन चावल, 20 लाख टन गेहूं for retailer दे रहे हैं, ताकि flood किया जा सके। दाम कितना तय किया, MSP plus freight charge. दोनों को add कर दिया, तो वह कीमत 15 रुपए से अधिक हो गई। एक तो महंगाई से already परेशान हैं और आप उसको इस तरीके से बढ़ा रहे हैं।

आप लेवी शुगर की बात देखिए। कल मैं अपने बिहार के उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी से बात कर रहा था। उन्होंने मुझे एक बात बताई कि लेवी शुगर का कोटा सैंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। कौन सी स्टेट पीडीएस के लिए

लेवी शुगर कहां से उठाई जाएगी, यह भी सैंट्रल गवर्नमेंट ही बताती है। अब फैक्ट्री बिहार में है, ईस्टर्न यूपी में है, लेकिन वहां से बिहार को टैग नहीं किया गया। बिहार को टैग किया गया महाराष्ट्र से। अब जिन-जिन फैक्ट्रियों का नाम था, जब बिहार के ऑफिसर्स महाराष्ट्र में वहां गए, तो उनको कहा गया कि हमारा कोटा एग्जॉस्ट हो गया, आप देर से आए हैं। आप फ्रेट चार्ज की बात भूल जाइए, आप यह बताइए कि बिहार के लेवी शुगर का कोटा महाराष्ट्र से क्यों उठाना चाहिए और उसका फ्रेट चार्ज क्यों बढ़ना चाहिए। यह कौन सा वेस्टिड इंटरेस्ट है? जनार्दन जी, आप आ गए, मैं आपको ही देख रहा था। मैंने आपका वक्तव्य पढ़ा था। समस्या बताने वाले समस्या का निदान भी तो बताएं। आज मैं उन समस्याओं को गिना रहा हूं, लेकिन आप यह कभी न भूलिए कि यह सरकार सिर्फ एनसीपी की नहीं है, यह सरकार आपकी भी है। मैंने सुना है कि आप हिन्दी के विद्वान भी हैं। "जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी इतिहास"। मैं कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान की जनता परेशान है। आप गरीबों की बात करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप मिडल क्लास में भी जाइए, आप जाइए रोहिणी में, जाइए कालका जी में, जिनकी तनख्वाह 25 हजार, 30 हजार या 40 हजार रुपए है, उनकी भी रसोई पर भी आज चोट पड़ रही है। लोग परेशानी में हैं।

आपने कहा था कि हम आम आदमी का दर्द मिटाएंगे, समाधान करेंगे, यह सरकार आम आदमी की है, लेकिन आम आदमी के साथ इतना बड़ा फरेब किया गया है। मैं अपनी बात यही कह कर समाप्त करूंगा, पांच साल आप आए, जनता ने आपको जिताया। तीन साल से महंगाई चल रही है, लेकिन अगर महंगाई आपसे नहीं संभलती तो कृपा करके आप गद्दी छोड़ दीजिए, देश का कल्याण होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजीव शुक्ल : उपसभाध्यक्ष जी, धन्यवाद ...(**व्यवधान**)... इनको जवाब तो हम ही दे सकते हैं और कौन इनको जवाब देगा ...(**व्यवधान**)... इनको तो जवाब हम ही दे सकते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Please, Please ...*(Interruptions)*... No-no ...*(Interruptions)*... You start ...*(Interruptions)*... Please ...*(Interruptions)*...

श्री राजीव शुक्ल: इनको तो हम ही को जवाब देना पड़ेगा।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Please start. ...*(Interruptions)*...

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, उत्तर शिष्ट भाषा में ही होना चाहिए। यह आपत्ति मैं पहले से ही दर्ज कर रहा हूं। I need your protection.

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र) : मैं बोलता ही शिष्ट भाषा हूं। ...(**व्यवधान**)... मैं अशिष्ट भाषा बोलता ही नहीं हूं। हम कांग्रेस के लोग हमेशा शिष्ट भाषा का ही प्रयोग करते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। सुबह से जो भी वक्ता उधर से शुरू हो रहा है, एक ही बात कह रहा है कि महंगाई पर आठ बार बहस हुई है, कोई कहता है कि नौ बार बहस हुई है और कोई कहता है कि सात बार बहस हुई है। मैं लाइब्रेरी से रिकॉर्ड निकाल कर लाया हूं। पिछले आठ साल में इस विषय पर 83 बार बहस हुई है, यानी कि हर साल महंगाई पर बहस हुई है। एनडीए के जमाने में भी सात बार महंगाई पर बहस हुई है। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यूपीए सरकार में ही महंगाई पर बहस हो रही है, हर सरकार में महंगाई पर बहस हुई है। इसलिए कोई बड़ा तूफान खड़ा नहीं हो गया है कि महंगाई पर बहस हुई। ऐसी कोई बात नहीं है।

मान्यवर, हमें इस बात की खुशी है कि उस कोने से लेकर इस कोने तक, सबमें एक बात पर सहमति है कि हम सब महंगाई से चिंतित हैं। इससे जितनी तक़लीफ माननीय नेता विपक्ष को है, उतनी ही तकलीफ नेता सदन को भी है और हम सबको भी है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई खुशी है या हम महंगाई को डिफैंड कर रहे हैं। ऐसा कतई नहीं है। जिस दिन यह प्रस्ताव आया कि महंगाई पर बहस होनी चाहिए, सबसे पहले हम लोगों ने ही कहा कि प्रश्नकाल भले ही स्थगित कर दीजिए, लेकिन महंगाई पर बहस कीजिए। हम बात करने को तैयार हैं और हर सत्र में जब-जब यह बात आई, महंगाई पर बहस करने के लिए सरकार हर बार बराबर तैयार हुई। इसका मतलब यह है कि महंगाई पर हम भी उतने ही चिंतित हैं, जितने आप हैं। हम खुद भी यही चाहते हैं कि महंगाई रुके, लेकिन इसके लिए हमें इसके कारणों में हमें जाना पड़ेगा। 60 सालों में ऐसा कोई वर्ष नहीं है, जिसमें महंगाई पीछे चली गई हो। एक गति से महंगाई बढ़ती ही रही है। लेकिन अगर कहीं ज्यादा इज़ाफा हुआ है, तो उस पर निश्चित रूप से बहस करने की जरूरत है और उसको एड्रेस करने की जरूरत है। हम खुद आप सबकी बात से सहमत हैं, चाहे वृंदा जी हों, चाहे जेटली जी हों, चाहे सदन के अन्य सदस्य हों। हम आपके सामने यही बात रखना चाहते हैं कि आखिर इसकी क्या वजह है। इसकी चार-पांच वजह हैं। एक तो यह बात बिल्कुल तय है कि विश्व बाजार में खाने के पदार्थों की कीमतें बहुत बढ़ी हैं, भले ही आप हंस कर या कैसे भी इस बात को डिसमिस कर दीजिए। आज जितने भी गरीब मुल्क हैं, चाहे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, वहां हमसे ज्यादा दाम बढ़े हैं, लेकिन इसे हम कोई खुशी की बात नहीं मानते हैं।

वे चाहे धनी देश हों या निर्धन देश हों, विश्व में हर तरफ कीमतें बढ़ी हैं। वर्ल्ड बैंक का data भी यह कहता है कि आज 850 मिलियन लोग भुखमरी के कगार पर हैं और 15 करोड़ बाद में बढ़े हैं। इस प्रकार विश्व में एक अरब लोग already भुखमरी के कगार पर हैं। इसका मतलब यह है कि यह संकट सब तरफ है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि यहां पर कुछ हो गया और उसकी वजह से एक वह असर है।

दूसरी बात यह है कि अपने यहां सब जानते हैं कि rains की short fall हुई। बारिश कम हुई जिससे सूखे की स्थिति आई। उसका भी असर खेती के उत्पादन पर पड़ा है।

तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि demand and supply में जो gap रहा ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती वृंदा कारत : राजीव जी, एक मिनट। ...(**व्यवधान**)... आपने global inflation की बात की। ...(**व्यवधान**)... अगर आप G-20 का latest आंकड़ा देखिए तो ...(**व्यवधान**)... Out of G-20 nations, India's consumer price inflation ratio is 14.97 per cent; Russia, 8.8 per cent; Argentina, 7.7 per cent; Turkey, 6.5 per cent; South Africa, 6.3 per cent; Brazil, 4.3 per cent; Saudi Arab, 4.2 per cent; Mexico, 3.6 per cent; and China, 1.9 per cent. ...*(Interruptions)*... This data pertains to consumer price inflation. So, please do not mislead the House. This is what I am saying. ...*(Interruptions)*...

श्री राजीव शुक्ल: वृंदा जी, हमारे पास भी सारी कंट्रीज़ का रिकॉर्ड है। नॉर्थ अमेरिका से लेकर साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, एशिया यानी पूरा with graph and data सब हम बना कर लाए हैं। हम तो इस बहस में पड़ना ही नहीं चाहते। हम उस बहस में तब पड़ें जब आपसे हमारी कहीं नाइत्तिफाकी हो। ...(**व्यवधान**)... उपसभाध्यक्ष जी, मैं उस बहस में पड़ना नहीं चाहता हूं। मैं उस बहस में तब पंडूँ जब उधर से या आपसे हमारी नाइत्तिफाकी हो। ...(**व्यवधान**)...

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand): Sir, my learned friend, Mr. Shukla, knows too much about economics. Can he name any country that is having higher consumer price index than India? Name any country.

श्री राजीव शुक्ल : पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्ला, बर्मा आदि चार-चार कंट्रीज़ के नाम मैं ले रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Otherwise, before coming to the House, just see the 'pricecheck.com'.

श्री राजीव शुक्ल : मैं अपने अड़ोस-पड़ोस के चार कंट्रीज़ के नाम ले रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI S.S. AHLUWALIA : Please do not mislead the House.

श्री राजीव शुक्ल: अहलुवालिया जी, मैंने चार-चार कंट्रीज़ के नाम लिए हैं। ...(**व्यवधान**)... मैंने एक नहीं बल्कि चार कंट्रीज़ के नाम लिए हैं। ...(**व्यवधान**)... ये हमारे neighbouring countries हैं। ...(**व्यवधान**)... मैंने चारों neighbouring countries के नाम लिए हैं। ...(**व्यवधान**)... मेरा दावा भी नहीं कि मैं आपकी तरह एक अर्थशास्त्री हूं ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Shukla, please do not respond to him. You address the Chair. ...*(Interruptions)*... Do not respond to these questions and address the Chair. You say what you want to say. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAJEEV SHUKLA: Sir, he is the Deputy Leader of the main Opposition Party. I have to respond to him. वह अपने आंकड़े अपने घर पर कम्प्यूटर पर बनाते हैं। He is also a tweeter. ...*(Interruptions)*... नहीं, इनको tweeter के लिए नहीं मिला ...(**व्यवधान**)... वह करण जौहर को मिला है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): The are trying to interrupt your speech. ...*(Interruptions)*...

श्री राजीव शुक्ल : एक बात जिसको बहुत हल्के से सदन में हमारे मित्र, नेता विपक्ष, ने कह दिया कि कहा जाता है कि MSP बढ़ा। MSP कोई साधारण नहीं बढ़ा है। निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा। हमें खुशी है कि MSP बढ़ा। अगर उसका असर महंगाई पर आता है तो थोड़ा बहुत आने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे किसान भाईयों को कोई मदद मिलती है तो यह कोई गलत बात नहीं है। इसमें इस तरह की कोई बात नहीं कि कोई बहुत बड़ा स्कैंडल कर दिया गया।

मैं बताता हूं कि MSP में कितना फर्क आया है। आप यह देखिए कि 2005-2006 में गेहूं का समर्थन मूल्य 700 रुपए प्रति क्विंटल था और सरकार ने उसे बढ़ा कर 1100 रुपए किया। आप इसमें jump देखिए। ...(**व्यवधान**)... दूसरा, paddy पर, धान पर 600 रुपए से बढ़ा कर 1050 रुपए किया गया। Sugarcane 260 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। जब किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ता है तो उसका असर आता ही है। लेकिन, मैं यही कहता हूं कि जो आज की प्राइस है, उसके लिए सिर्फ ये ही जिम्मेदार हैं। मैं यह बात नहीं कह रहा हूं। मैंने उसके कुछ और कारण भी रखे हैं। उसके और भी तमाम कारण हैं। लेकिन, उसका यह भी एक कारण है। किसानों को देना चाहिए और इसका कहीं-न-कहीं appreciation मिलना चाहिए। अगर किसानों का कर्ज माफ होता, अगर उनको ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत धन मिलता, उसका appreciation भी होना चाहिए।

हर चीज की सिर्फ लगातार आलोचना करने और हम पर प्रश्नों की बौछार करने से कोई समाधान नहीं निकलता। हम आपकी बात से सहमत हैं और हम सब भी उतने ही चिंतित हैं। मान्यवर, इसलिए मेरा यह कहना है कि एम.एस.पी. एक बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती वृंदा कारत : इसीलिए आपने fertilizer के दाम बढ़ा दिये? ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Brindaji, please let him speak because there is a shortage of time.

श्री राजीव शुक्ल : वृंदा जी, अगर पूरे देश में कहीं fertilizers पर टैक्स लगता है तो जैसा अभी हमारे मित्र बता रहे थे यह सिर्फ गुजरात में लगता है। ऐसी कोई बात नहीं है। हर राज्य को अपनी-अपनी इकोनॉमी देखनी पड़ती है।

श्री अरुण जेटली : गुजरात का agricultural growth rate 14 परसेंट है।

श्री राजीव शुक्ल : वहां agricultural growth तो है, लेकिन वहां महंगाई तो वैसी ही है। Agricultural growth rate से क्या होता है? सबसे ज्यादा VAT भी वहीं है।

मान्यवर, विश्व में एक बिलियन लोग भुखमरी की कगार पर हैं। भारत में खाने के तेल की कमी ऐतिहासिक है। यह कोई आज की बात नहीं है। यह उस सरकार में भी थी। मुझे याद है कि जब श्री नीतिश कुमार जी कृषि मंत्री थे तब उनको भी इसे इम्पोर्ट करना पड़ा था। भारत में क्रूड पाम ऑयल, खाने के तेल और दलहन की हमेशा से कमी रही है। इंदिरा जी अपने हर भाषण में इनके बारे में कहती थीं। बीस सूत्री कार्यक्रम में भी उनका यही कहना होता था कि दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाओ। यह शुरू से इस देश की समस्या रही है और आज फिर वही उभर कर सामने आई है। इसीलिए 9 मिलियन टन क्रूड ऑयल आयात किया जा रहा है और इस पर "जीरो" ड्यूटी कर दी गई है। अगर इसे कोई प्राइवेट रूप से भी लाना चाहता है तो वह ला सकता है, क्योंकि इसकी कमी को खत्म करना है। हम उस पर Public Distribution System के जरिये सब्सिडी दे रहे हैं। 3 मिलियन टन दालों का आयात तत्काल एक महीने के अंदर किया जा रहा है। पीडीएस की जितनी shops हैं, निश्चित रूप से वे उन सब में पहुंच जाएंगी। 5 लाख टन गेहूं और चावल आ गया है जो सब जगह भेजा जा रहा है। जहां तक कदम उठाने की बात है, तो इस किस्म के सारे कदम उठाये जा रहे हैं ताकि आयात के जरिये डिमांड और सप्लाई के गैप को पूरा किया जा सके। यह सरकार अपनी तरफ से इन मामलों पर सारे कदम उठा रही है।

यहां पर एक बात future trading के बारे में भी उठायी गई है। Future trading पहले थी, लेकिन 2007-08 में चावल, उड़द और तूर, तीनों पर future trading suspend कर दी गई। सुगर पर यह 2009 में suspend कर दी गई। अगर सिर्फ future trading को बदनाम करना है कि उसके कारण महंगाई है तो मुझे लगता है कि यह उचित नहीं है, क्योंकि पिछले साल इसको भी समाप्त कर दिया गया था।

अब एक बात यह कही जाती है कि यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, इसे राज्य सरकारों पर क्यों डाला जा रहा है? मैं नहीं समझता कि केन्द्र सरकार इसे कहीं excuse के रूप में ले रही है। जब-जब Parliamentary party की मीटिंग हुई, उसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने हमेशा केन्द्र सरकार से कहा कि महंगाई को रोकिए। वह खुद बहुत चिंतित रहती हैं। वे लगातार इस चीज़ को दो-तीन सालों से बोलती चली आ रही हैं। हम अपनी ओर से इस बात को राज्य सरकारों पर इसलिए नहीं टाल रहे कि हम कोई blame game खेल रहे हैं या किसी के ऊपर

दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन जरा दिल पर हाथ रख कर यह बताइए कि क्या महंगाई को रोकने में राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? इंदिरा जी के समय से सभी मुख्य मंत्री कांग्रेस के होते थे, फिर भी वे उन्हें पत्र लिखती थीं कि महंगाई पर काबू लाया जाए। राम गोपाल जी, आप यहां बैठे हैं, आप जानते हैं कि 3/7 क्या होता है। अगर कोई 3/7 लागू करता है तो वह राज्य सरकारें लागू करती हैं। अगर राज्य सरकारें हाथ झाड़ कर बैठ जाएं और सारे मुख्य मंत्री यह समझें कि उनका काम सिर्फ यह है कि जमीनें अलॉट करो, तो यह गलत है। महंगाई को रोकने में जितनी केन्द्र सरकार की भूमिका है, उतनी ही भूमिका राज्य सरकारों की भी है। चाहे हमारी सरकार हो, चाहे इनकी सरकार हो या चाहे उनकी सरकार हो। जमाखोरों पर नियंत्रण करने का काम सिर्फ राज्य सरकारें कर सकती हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री ब्रजेश पाठक : जहां आपकी सरकारें हैं, वहां क्या हो रहा है? ...(**व्यवधान**)...

श्री राजेश शुक्ल : पाठक जी, ऐसा नहीं है कि हम अपनी सरकारों को defend कर रहे हैं। हम अपनी सरकारों को भी कह रहे हैं। हम अपने मुख्य मंत्रियों को भी कह रहे हैं कि आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। अगर सब मिल कर काम करें, जैसे आप आतंकवाद को रोकने के लिए करते हैं, जैसे आप नक्सलाइट्स से लड़ने के लिए करते हैं, उसी तरह महंगाई से सबको मिल कर लड़ना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ इसी तरह एक-दूसरे पर दोषारोपण करते रहे तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग स्थिति है। ...(**व्यवधान**)... आप यह बताइए कि अगर इसमें राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है तो सब्जियों के दाम क्यों बढ़ते हैं? यह एक बहुत बड़ी समस्या है। एक राज्य में सब्जी का एक दाम रहता है और दूसरी जगह दूसरा दाम रहता है। ऐसा क्यों होता है? सब्जियों के दाम को तो local administration सम्भाल सकता है? तो सब्जियों के दाम भी बढ़ते हैं और उससे लोग बहुत दुखी रहते हैं। यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर भी आती है, मुख्य मंत्रियों की भी जिम्मेदारी है कि वे इस पर सख्ती करें। जो राज्य सरकारें capable हैं, वे कर रही हैं, जैसे उन्होंने कहा कि 17% सिर्फ UPA की सरकारों ने किया, बाकी non UPA Goverments ने raid कीं, लेकिन raids के बाद charge sheet कितनी दाखिल हुईं, prosecutions कितने हुए, वह important है। उस ratio में non UPA govermnemts बहुत नीचे हैं, खास तौर से BJP led governments. आपने raid का तो नाटक कर दिया, लेकिन उसके बाद prosecution कितना किया, वह भी उतना ही important है, उस तरफ भी आपको देखना चाहिए। उसके आंकड़े बिलकुल स्पष्ट हैं, आपको भी पता है, हमको भी पता है और ट्रेडर्स अगर फायदा ले रहे हैं, यह कहा जाता है और एक अखबार लगातार क्वोट किया जा रहा है *Times of India* कि किसान को यह मिलता है और उसको यह दिया जाता है। तो यह तो सीधे-सीधे राज्य सरकारों के हाथ में है कि आपके यहां जो *भाटिया* होता है, बिचौलिया, उसको पकड़िए, किसने रोका है? एक SP चाहे तो हर जिले के *भाटिया* या बिचौलिए को उठाकर बंद कर सकता है। क्या उसके लिए मनमोहन सिंह जी की जरूरत है या भारत सरकार के गृह सचिव या चिदम्बरम जी की आवश्यकता है? वह तो सीधे-सीधे Collector और SP के हाथ में है कि उस बिचौलिए को पकड़ें जो गांव से सब्जी, दाल, गेहूं आदि को लेकर यह सब कर रहा है। मैं यह किसी एक सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, यहां पर सारी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, यह सबसे बड़ी चीज हमें समझनी पड़ेगी और लोगों पर VAT कम करना पड़ेगा।

इसके बाद मैं कुछ बातें ऐसी रखना चाहता हूं जो सबके लिए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई एक बहुत चिंतनीय विषय है और एक ऐतिहासिक सच यह है कि इस देश में गांव और शहर में लोग बढ़ रहे हैं। जो कृषि योग्य जमीन है, खेती की जमीन है, वह कम होती जा रही है और जनसंख्या बढ़ रही है, खाने वाले बढ़ रहे हैं। यह समस्या पूरे राष्ट्र की है, किसी की भी सरकार हो, चाहे वह हमारी सरकार हो या किसी और दल की सरकार हो, इस

समस्या का सामना सबको आगे चलकर करना पड़ेगा। तीन साल पहले हम 50 हजार करोड़ रुपए की फूड आइटम का इम्पोर्ट करते थे, अब 2 लाख करोड़ रुपए के फूड आइटम्स इम्पोर्ट होने की नौबत आ गई है और जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, शहर बढ़ते जाएंगे, खेती की जमीन कम होती जाएगी, यह नौबत और बढ़ती जाएगी। इसलिए एक नीतिगत निर्णय हर राज्य सरकार को, केन्द्र सरकार को, सबको लेना होगा कि जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, नया डेवलपमेंट है, नई हाऊसिंग कालोनीज़ हैं, नए जितने भी प्रोजेक्ट हैं, कोशिश यही हो कि वे waste land पर हों, वे waste land पर आएं, जो ऊसर जमीन है, जो खेती योग्य जमीन नहीं है, उस पर लाए जाएं और इसको प्राथमिकता दी जाए। श्री राजीव गांधी जी ने इसका एक अलग से मंत्रालय बनाया था। इंडिया में 27% waste land है, बहुत ज्यादा waste land है। इसलिए नया जो डेवलपमेंट हो, चाहे वह औद्योगिक हो या कैसा भी हो, उसमें waste land को प्राथमिकता दी जाए, खेती की जमीन को छुआ न जाए और कोशिश यह की जाए कि खेती की जमीन आगे न घटे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो आगे आने वाले बढ़ेंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हर राज्य सरकार इस पर ध्यान दे कि जो waste land है, जो ऊसर जमीन है, बंजर जमीन है, उस पर नए प्रोजेक्ट्स आएं। इससे उस waste land का डेवलपमेंट भी हो जाएगा और खेती की जमीन भी कम नहीं होगी। यह एक पॉलिसी का विषय है, जिसके लिए मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं।

दूसरा, मैं यह देख रहा था कि लाखों पार्टियां रोज़ होती हैं, चाहे वह शादी-ब्याह की हों या किसी अन्य प्रकार की हों, तो यह भी एक सोचने का विषय है क्योंकि इन लाखों पार्टियों में पूरे देश में हजारों क्विंटल खाद्य पदार्थ रोज बर्बाद होता है। जब इतने लोग भुखमरी के कगार पर हैं, इतना महंगा अनाज है, तो कहीं न कहीं इस पर भी सोचना पड़ेगा कि जो पूरे देश में लाखों दावतें होती हैं, चाहे फाइव स्टार में देख लो या कहीं और, पूरे देश में लाखों दावतें रोज़ होती हैं और हजारों क्विंटल खाना बर्बाद होता है कि आप देखते रह जाते हैं। उस waste food का कोई इस्तेमाल नहीं होता। उस waste land के management के लिए भी सब पार्टियों को, सारी सरकारों को, चाहे राज्य की हों या केन्द्र की, सोचना पड़ेगा।

तीसरा सुझाव मेरा यह है, श्री एन.के. सिंह जी यहां बैठे हुए हैं, जब ये रिवेन्यु सैक्रेट्री थे, तब इन्होंने इस बात को रखा था और काफी कोशिश कराई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी, इसको हम फिर दोहराना चाहते हैं - cold storage chains के development की। इसको हम फिर से दोहराना चाहते हैं कि cold storage chains को देशव्यापी स्तर पर हमें विकसित करना पड़ेगा, जहां हमारा जो perishable food है, जो नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ हैं, उनको हम बचाकर रख सकते हैं, जिनकी अभी हमारे पास पूरे देश में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। ये तीन सुझाव मेरे सरकार की तरफ से हैं।

महंगाई हम सबकी चिंता है, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, अकेले प्रधान मंत्री को दोष मत दीजिए, हर मुख्य मंत्री आगे खड़ा हो कि मैं भी हल करूंगा, हम भी हल करेंगे, तभी इस समस्या का हल होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI M.V. MYSURA REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman Sir, all of us know that the prime responsibility of the Government is to provide food security to the *aam admi,* but this requires proper management of food grains. This involves procurement from farmers at appropriate remunerative prices, distribution among customers at reasonable prices and maintenance of buffer for price stability. Sir, this Government has failed in achieving these three objectives because of their

ad hoc decisions and flip-flop and lopsided policies. One classic example is that on New Year's day India had 4.8 crore tonnes of food grains with the public agencies against the buffer stock norm of two crore tonnes, but it is a million dollar question, why the Government is not offloading, at least, 50-60 lakh tonnes of wheat and rice into the market. This quantity is only a meagre part of the stock which is more than the buffer stock. Even though the Cabinet Committee decided to release 20-30 lakh tonnes into the open market, the Government gives one excuse that the States are not lifting the allocated food grains under the open market scheme. Here, I wish to bring it to the notice of the hon. Minister and Government, through you, Sir, that the rate quoted by the Government is arrived at after adding the milling cost, commission, transport, storage cost etc., which is almost equal to the price outside. So, no Government is lifting these stocks, if the Government-quoted price had been paid to the farmers, surely the prices in the open market would have come down to Rs.13 per kg for wheat and Rs. 20 per kg for rice. The hon. Prime Minister had convened a meeting of the Chief Ministers and one of the decisions taken there was to take action against hoarders. In this case, the real hoarder is the FCI, the Government itself. So, the Chief Ministers need to take action against this Government and not the hoarders, because they are holding huge quantities of more than two crores over and above the buffer norms without releasing limited stocks under the open market scheme, with a proper priced scheme.

Sir, another point is about sugarcane. Even there the same thing happened with a reversal– right decisions were taken at the wrong time. This was explained by Shri Arun Jaitley and Shrimati Brinda Karat. There is no need for me to repeat these things. It is because of the failure of the Government that the present crisis in sugar prices has occurred. Sir, even the last time, during the debate on price rise, I had spoken elaborately on this point; prices at the farm gate are always lower for all food grains while the retail prices are always exorbitant for the consumers. Because of such policies, only middlemen are benefited. All the speculators and hoarders are benefiting from this. The Government is not taking any action on or looking into such problems. Government is not initiating any action to rectify this problem. Why is there a less rate at the time of production at the farm gate? Why do consumers have to pay a greater price at the retail market? The Government needs to look into some of these policies and take measures in this regard; otherwise, the same problem would recur. To prevent such things, Government must do strategic policy planning to encourage procurement directly from the farmers' fields and establish effective linkage to retail chains.

Only then they can contain the price rise and bring stability in price rise. But the Government may be thinking that because of the inclusive growth there is a purchasing power at the ground level in the hands of poor men. But it is not so. The worst sufferers are unorganised sectors. Somehow

organised sectors are getting some protection from the Government, but unorganised sectors are the worst sufferers. I request the Government to take effective measures to control price rise. Thank you.

श्रीमती माया सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, महंगाई का सवाल मानवीय पीड़ा का सवाल है और इस पर किसी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम लोग इसको राजनीतिक नजरिए से न देखें। इसी कारण एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते समूचे विपक्ष ने एकजुटता के साथ संसद के सारे कामों को रोक कर इस महंगाई पर चर्चा कराने की मांग रखी। दो दिन तक सत्ता पक्ष ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और आज इसे स्वीकार किया है। आज इस ज्वलंत विषय महंगाई पर चर्चा हो रही है। आपने इस पर मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं और धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

उपसभाध्यक्ष जी, महंगाई ने इतना विकराल रूप ले लिया है कि इसकी विकरालता को नापने के सारे पैमाने टूट चुके हैं। इस महंगाई ने पूरे देश को इस कदर गिरफ्त में ले लिया है कि इसको आंकड़ों में बांधना अब संभव नहीं रहा है। यूपीए सरकार आम आदमी की हितैशी होने का दावा करती है, लेकिन उसने आम आदमी के साथ जो असंवेदनशीलता और गैर-जिम्मेदारी निभाई है, साबित की है, उसे मैं एक आपराधिक कृत्य मानती हूं।

उपसभाध्यक्ष जी, एक तरफ तो प्रधान मंत्री जी मान रहे हैं कि हमारे देश में स्थिति गंभीर है और दूसरी तरफ वे किसी को भी भूखे सोने नहीं देंगे, इसका वायदा भी कर रहे हैं, लेकिन जब कि हकीकत यह है कि हमारे देश का हर चौथा व्यक्ति भूखा है और बढ़ती महंगाई ने आग में घी डालने का काम किया है। आज स्थिति इतनी चिंताजनक हो गई है। प्रधान मंत्री जी संरक्षित खाद्यान्न के भरोसे जो बढ़ते मूल्य हैं, उन मूल्यों पर काबू पाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि जो खाद्यान्न संरक्षित हैं, वह बाजार में किस मूल्य पर बिक रहा है और उस अनाज को खरीदने की क्षमता आम व्यक्ति में बची है या नहीं बची है। इसके साथ ही साथ, "नरेगा" की उपलब्धि तो आप खुद लेना चाहते हैं, लेकिन जब बढ़ी कीमतों की बात आती है, तो फिर आप कहते हैं कि इसकी कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। यह दोहरी नीति अच्छी बात नहीं है और यह नहीं चलेगी। आपको इस महंगाई पर काबू पाने के प्रयास करने ही होंगे।

इसके साथ ही बुंदेलखंड की बात है। एक तरफ तो आप सूखे पर नियंत्रण करने के लिए Central Authority बनाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कालाहांडी के नाम पर आप बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। मैं कोई राज्य सरकारों का पक्ष नहीं ले रही हूं, लेकिन देश की कृषि क्षेत्र की जो नीतियां हैं, जिन्हें केन्द्र सरकार बनाती है और जब आप इस मोर्चे पर असफल होते हैं, तो सारा दोष राज्य सरकारों के ऊपर मढ़ देते हैं। यह कोई वोट लेने का मुद्दा नहीं है। मैं आग्रह करूंगी कि इस तरह की राजनीति न करें, क्योंकि यह आम भूखे जनता के पेट का सवाल है। यह बहुत ही अहम लोगों की समस्या है और हमें सबसे पहले इसके निराकरण ढूंढने होंगे। एक तरफ सरकार वक्तव्य देती है कि खाद्य और भण्डार की स्थिति सुखद है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समय-समय पर मंत्रियों के माध्यम से जो घोषणाएं होती हैं, जो भी उनके वक्तव्य आते हैं और वे लोग जो वस्तुओं के आयात की बात करते हैं,

तो हमें आश्चर्य होता है कि एक तरफ आपके पास गेहूं का पर्याप्त स्टॉक है और दूसरी तरफ आप आस्ट्रेलिया से और विभिन्न देशों से खराब और महंगी कीमत पर अनाज खरीदते हैं। वह आयात किया जाता है और हमारे किसानों को उनकी पैदावार का, अनाज का उचित मूल्य भी हम नहीं दे पाते हैं। तो इस तरीके का जो विरोधाभास है... महोदय, ऐसी ही स्थिति दालों के मूल्य की है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इसके संबंध में बातें रखी हैं। दाल के मूल्य में जब भारी वृद्धि हो रही थी, तो उस वक्त सभी निर्देशों की अनदेखी करते हुए सरकार से शह पाने वाले बेईमान निर्यातकों को भारतीय दालों को निर्यात करने की छूट दे दी गई, ताकि वे भारी मुनाफा कमा सकें। हमारी पार्टी ने जब यह मामला उठाया, तब उसकी सी.बी.आई. जांच शुरू हुई, लेकिन मुझे अभी भी शक है कि सी.बी.आई. मुनाफाखोरों तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी? क्या उसके सही निर्णय हमारे सामने आ पाएंगे या नहीं?

महोदय, केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह कह कर तूफान खड़ा कर दिया कि हम चीनी का आयात करेंगे, जबकि हमारा देश चीनी का सबसे बड़ा निर्माता है और सबसे अधिक चीनी यहां होती है। इस घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के भाव 24 प्रतिशत बढ़ गए और इससे हमारे देश के अंदर जो चीनी आयात की गई, उसके लिए हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए मेरा आरोप है कि यू.पी.ए. सरकार के संरक्षण में घरेलू और विदेशी कंपनियां आजकल जो निर्देश दे रही हैं कि खाद्य पदार्थ कब और कितनी मात्रा में और किन परिस्थितियों में आयात किए जाएं और कब उन पर रोक लगाई जाए, यह भी निर्देश वही कर रही हैं, तो क्या सरकार ने अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति दलालों, बिचौलियों और खाद्यान्न के व्यापारियों या जमाखोरों के सामने समर्पित कर दी है? आज आम आदमी के साथ इतना बड़ा छल किया जा रहा है कि जो बड़ी-बड़ी कंपनियां और मुनाफाखोर हैं, वे फायदे में हैं और आज आम आदमी के लिए आटे-दाल की कीमतें इतनी महंगी हैं कि जो मजदूर है, वह प्रतिदिन सौ रुपया कमाता है, लेकिन सौ रुपए की दाल और पचास रुपए की चीनी वह कहां से खरीदेगा, इसकी ओर आपने कभी ध्यान नहीं दिया।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह बताना चाहूंगी कि हमारे समाज के कमजोर वर्ग के हालात इतने बदतर हैं कि भोजन की कमी के चलते इन परिवारों में जो बच्चे जन्मते हैं, उनमें 54 प्रतिशत नवजात शिशु औसतन वजन से कम होते हैं और इनमें प्रति हज़ार में से 83 बच्चे पैदा होकर ही मर जाते हैं। इसी तरीके से 1000 में से 119 बच्चे पांच साल के भीतर ही मर जाते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो कुपोषण का शिकार हो रही हैं, उनको कैलोरीज़ जितनी चाहिए उस के हिसाब से भोजन नहीं मिलता है और ये बच्चे, जो कम वजन के पैदा हो रहे हैं और इसके साथ-साथ मंद बुद्धि के बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, और इसकी तरफ अगर सरकार का ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि इस वर्ग के लोग भोजन के अधिकार का, जो न्यूनतम उनकी आवश्यकताएं हैं, वह भी ...(**व्यवधान**)...

MS. MABEL REBELLO (Jharkhand): Sir, malnutrition is highest in Madhya Pradesh. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): No, please don't disturb. ...*(Interruptions)*... You will have your chance. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती माया सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, इस वर्ग के लोगों के पास अनाज खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

MS. MABEL REBELLO: Sir, ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): You will get your chance and you can reply. ...*(Interruptions)*... Don't disturb.

श्रीमती माया सिंह : सर, मध्य प्रदेश में 65 व्यक्ति बी.पी.एल. कार्डधारी हैं और मांग के अनुसार केंद्र सरकार से 40 लाख व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या इन 20 लाख परिवारों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? मध्य प्रदेश की सरकार दो रुपए किलो गेहूं और चार रुपए किलो चावल के हिसाब से, अपनी सीमित क्षमताओं से उन लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा दे रही है। इसी तरीके से बी.पी.एल. परिवारों को एक रुपए किलो चावल के हिसाब से छत्तीसगढ़ की सरकार भी प्रति माह प्रति परिवार 35 रुपए किलो के हिसाब से उनको अनाज दे रही है। जहां-जहां हमारी पार्टी की सरकारें हैं, वहां भरपूर कोशिश हो रही है। लेकिन बड़े दुख और पीड़ा के साथ मैं इस सदन में कहना चाहती हूं कि जहां पर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स हैं, उनके साथ केन्द्र सरकार अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए और तो और हमारे जो मानवीय संबंध हैं, वे संबंध और सामाजिक समरसता भी इस महंगाई के कारण टूटकर बिखर रही है। महोदय, हमारी जो पुरानी परंपरा "अतिथि देवो भवः" की है, वह समाप्त हो रही है। आजकल अतिथि देवो नहीं, दानव के जैसे नज़र आने लगे हैं और लोग उनसे बचने लगे हैं कि अतिथि हमारे घर न आएं तो ज्यादा अच्छा है। इसी तरीके से महंगाई से त्रस्त होकर परिवार सहित लोग आत्महत्या करने को विवश हो रहे हैं। वहीं भूख के कारण परिवारों में आपस में झगड़े हो रहे हैं, आपस में मार-पिटाई होती है। इससे वहां पर कानून-व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि बाढ़ और अकाल जैसी प्राकृतिक आपदा से भी भयंकर आपदा का स्वरूप इस महंगाई ने ले लिया है। इसलिए यूपीए सरकार की गलत नीतियों और गैर-जिम्मेदारी के कारण जो महंगाई की समस्या उत्पन्न हुई है, मैं आग्रह करूंगी कि इसे राष्ट्रीय आपदा के रूप में देखा जाना चाहिए और इसको तत्काल दूर करने के उपाय करने चाहिए। महोदय, मैं यहां पर एक वाकया बताना चाहती हूं। यह मज़ाक की बात नहीं है, सही स्थिति है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि दो महिलाएं पुलिस थाने पहुंची थीं। पुलिस इंस्पेक्टर ने उनसे पूछा कि मैडम, आप किस बारे में रिपोर्ट लिखवाना चाहती हैं? क्या आपका पर्स चोरी हो गया है या गले की चेन खींच ली गई है? वह रिपोर्ट लिखने लगा। तब महिलाओं ने कहा, दारोगा जी, हमारा पर्स चोरी नहीं हुआ और न ही किसी ने हमारी चेन ली है। हम लोगों ने दो-दो किलो आलू खरीदे थे। उस आलू की थैली को ही कोई छीनकर ले गया, भाग गया। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि इस सरकार के राज में सब्जी-भाजी के लिए भी सुरक्षा की व्यवस्थाएं करनी पडेंगी। इसलिए जैसा मैंने पहले भी कहा कि महंगाई जैसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह सवाल करोड़ों लोगों की पीड़ा का है और इस पीड़ा को आज यह सारा सदन यहां चेयर के माध्यम से व्यक्त कर रहा है, जिससे यूपीए सरकार पूरे तरीके से मुंह फेरे बैठी हुई है। आर्थिक विकास के सब्जबाग दिखाने वाली यह सरकार खाद्यान्न गारंटी बिल की बात करती है लेकिन उसको यह होश नहीं है कि अन्न पैदा करने वाला जो किसान और मजदूर है, उसको स्वयं को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, वह खाद्यान्न पैदा करने की स्थिति में नहीं है। आप उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं तो किस तरह से आप इतनी बड़ी समस्या से निजात पाएंगे? मैं अपनी वेदना को अभिव्यक्त करते हुए यह मांग करना चाहती हूं कि इस समस्या को राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए सरकार इसका हल निकाले अन्यथा सरकार में रहने का उसका जो हक है, उस हक को उसे छोड़ देना चाहिए। इतना कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान) : सर, "दानव" शब्द को हटा दिया जाना चाहिए। अतिथि दानव कभी नहीं लगता। ...(**व्यवधान**)... "अतिथि देवो भवः" होता है। माया सिंह जी ने कहा कि अतिथि आए तो दानव जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई राक्षस आ गया है। हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं लगता इसलिए "दानव" शब्द को इसमें से हटा देना चाहिए ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): I will examine it. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती माया सिंह : जिनको खाना नहीं मिल रहा है, मैंने उनकी स्थिति बयान की है।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): It is unparliamentary, I will remove it. I will examine it. ...*(Interruptions)*... देखेंगे। I will examine it.

श्री राशिद अल्वी : सर, महंगाई एक अहम मुद्दा है, महंगाई से गरीब आदमी, अमीर आदमी सब जूझ रहे हैं, इसमें कहीं कोई शुबहा नहीं है लेकिन यह सिर्फ हिन्दुस्तान के अंदर नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर है। पिछले 70 साल से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरी दुनिया में दस बड़े रिसेशन आए। 1929 के अंदर इससे ज्यादा बुरे हालात थे। उसके बाद आज जिन हालात से पूरी दुनिया गुजर रही है वह मुश्किल हालात हैं। अमेरिका के अंदर ...(**व्यवधान**)... अब आप सुनिए, उसके बाद बोलिए क्योंकि मुझे बीच में टोक रहे हैं।

अमेरिका के अंदर एक रिपोर्ट के मुताबिक 22,000 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। अमेरिकन गवर्नमेंट 6,000-7,000 बिलियन डॉलर्स मांगती है। लोग कहते हैं उससे ज्यादा का है। यहां बार-बार चायना का जिक्र किया जाता है। तीन लाख लोगों ने नौकरी खोई। चायना एक बंद होल की तरह है जिसकी खबरें आसानी के साथ बाहर नहीं आतीं। जो खबर वे देना चाहते हैं, देते हैं, जो नहीं देना चाहते वह नहीं देते हैं। हिन्दुस्तान का कोई मुकाबला चायना से नहीं किया जा सकता है। हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। चायना से उसका कोई मुकाबला नहीं है लेकिन चायना भी इस हालात से गुजर रहा है। सर, आज दुबई ही हालत किसी से छिपी नहीं है। दुबई तबाह हो गया है। दुबई में सर्विस सैक्टर के अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं था। आज दुबई से लोग छोड़-छोड़ कर जा रहे हैं। तो यह कहना है कि सिर्फ हिन्दुस्तान के अंदर ही महंगाई है, दुनिया के दूसरे इलाकों के अंदर नहीं हो रही है, यह गलत है। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रकाश जावडेकर (महाराष्ट्र) : आदर्श नहीं है, हकीकत है। ...(**व्यवधान**)... आदर्श सिर्फ आप लोगों का है। ...(**व्यवधान**)...

श्री राशिद अल्वी : मैं जानता हूं आप बहुत मौहब्बत करते हैं। कल को आप भी बोलेंगे इसलिए मुझे बोलने दीजिए तो ज्यादा अच्छा है।

उपसभाध्यक्ष (**प्रो. पी.जे. कुरियन**): बोलिए-बोलिए।

श्री राशिद अल्वी : सर, अभी किसी ने कहा था कि दुनिया के मुमालिक के नाम बताओ। पाकिस्तान के अंदर इंफ्लेशन 20 परसेंट से ज्यादा है। मेक्सिको के अंदर 121.46 डॉलर ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Mr. Rashid Alvi, don't get distracted by them. You please speak. ...*(Interruptions)*... Please don't disturb. Let his speak.

श्री राशिद अल्वी : मेक्सिको में 121 डॉलर पर-मीट्रिक टन से कीमत बढ़कर 256 मीट्रिक टन कीमत पहुंची। मैं गेहूं की कीमत की बात कर रहा हूं। थाईलैंड के अंदर चावल की कीमत 299 डॉलर मीट्रिक टन से बढ़कर 555 मीट्रिक टन पहुंच गई। सर, यह दुनिया की हालत है। हमारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को महंगाई से बहुत परेशानी है, परेशानी हमें भी है। सर, इस देश के अंदर डीजल की कीमत पहली बार 1965 के अंदर एक

पैसा बढ़ी थी। मैंने अपोजिशन के लोगों की वह तकरीरें पढ़ी हैं, जितना हाहाकार आज मच रहा है, उतना ही हाहाकार उस वक्त मचा था जब कीमत एक पैसे बढ़ी थी। सन् 1985 के अंदर डीजल की कीमत एक रुपया उन्नीस पैसे बढ़ी। तब की भी मैंने वह तकरीरें रिकार्ड के अंदर पढ़ी हैं। उस समय भी उतना ही शोर मचा था जितना आज मच रहा है। लेकिन सर, सन् 2000 के अंदर हमारे बी.जे.पी. भाईयों की सरकार थी, उस समय 2000 के अंदर अचानक डीजल की कीमत 11 रुपए 37 पैसे बढ़ी थी। जो लोग आज महंगाई की बात कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जब आती है तो महंगाई बढ़ती चली जाती है। ...(**व्यवधान**)... उस पर आ रहा हूं, फिक्र मत कीजिए। डीजल की वजह से किसान और उसकी खेती की जो कॉस्ट आती है उसका 60 फीसदी डीजल की वजह से होता है। उसका पानी, उसका इक्विपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन सबका मिलाकर डीजल की कीमत बढ़ने से किसान की लागत 60 फीसदी लागत सिर्फ डीजल की वजह से आती है। 11.37 रुपए 2000 के अंदर बढ़ाया ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Please let him speak. ...*(Interruptions)*... You address the Chair. Don't listen to them. ...*(Interruptions)*... No interruptions please. Listen to the speech. ...*(Interruptions)*...

श्री राशिद अल्वी : सर, यह हिंदुस्तान के अदंर पहली बार हुआ है कि आज सरकार बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को 2 लाख करोड़ से ज्यादा सब्सिडी दे रही है। आप सुनने की आदत डालिए। आप कीमतों से परेशान हैं, लेकिन चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं। 2000 के अंदर, जब पार्लियामेंट के अंदर बहस हुई ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): No comments please.

श्री राशिद अल्वी : अभी वे कह कर गए हैं कि हमारे जमाने में बहुत महंगाई नहीं थी, सस्ता था, सारी जनता खुश थी और उसके बाद भी 2004 के अंदर सरकार चली गई। हम में और आप में यह फर्क है। आज हमारे वक्त में महंगाई है, लेकिन देश की जनता हमारी नीयत को जानती है। वह जानती है कि सरकार भरसक कोशिश कर रही है। वह जानती है कि देश की स्थिति, दुनिया की स्थिति क्या है। आपको याद है कि मई, 1998 के अंदर आपने न्युक्लियर टेस्ट किया था, बड़ा काम किया था, यह इतिहास के अंदर लिखा जाएगा, लेकिन 1998 के अंदर आपकी प्याज की कीमत बढ़ी थी। देश के लोगों को आपकी नीयत पर शुबहा था और तीन स्टेट के अंदर आपकी सरकारें गिर गई थीं। आप मध्य प्रदेश में हारे, राजस्थान में हारे और दिल्ली के अंदर हारे। देश के लोगों को आप पर भरोसा नहीं था। आज महंगाई है, हम मानते हैं, लेकिन देश की जनता को हम पर भरोसा है। दो साल से महंगाई बढ़ रही है। दो साल से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन दो साल के अंदर कितने चुनाव हुए? इस मुल्क के अंदर दो साल में कौन-कौन सा चुनाव नहीं हुआ। देश की जनता हमारी नीयत के बारे में, सरकार की नीयत के बारे में जानती है। यह मसला सिर्फ हंसने का नहीं है। इस महंगाई के बावजूद हम दिल्ली का चुनाव जीते, चूंकि जनता जानती थी कि ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Raashidji, address the Chair.

श्री राशिद अल्वी : दिल्ली की जनता जानती थी कि हमारी नीयत साफ है, हम महंगाई से लड़ रहे हैं। हम हरियाणा जीते, हम महाराष्ट्र जीते, हम हिंदुस्तान का चुनाव जीते, पार्लियामेंट जीते। हमारे पास डेढ़ सौ सीटें थीं, हम जीतकर 206 सीटें लेकर आए। आज हमारे पास एक मजबूत सरकार है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): No running commentaries please.

श्री राशिद अल्वी : देश के अंदर महंगाई है, लेकिन देश की जनता को हम पर भरोसा है, आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। सर, मैं कोट करना चाहूंगा कि बीजेपी के लोगों को महंगाई से कितनी चिंता होती है। राम नाईक जी पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। कीमत बढ़ी, देश के अंदर हा-हाकार मचा, राम नाईक जी ने पार्लियामेंट के अंदर क्या कहा, मैं उसके दो जुमले पढ़कर सुनाता हूं। "It is true that this hike will certainly cause hardship for the common man." आम आदमी के लिए बहुत परेशानी होगी, लेकिन हम इसके बावजूद कीमत बढ़ाएंगे, "Presently, the population of this country has reached 100 crore. There is no such family or household which does not use kerosene or LPG and which will then have no other alternative except the forest food. It was kept in mind that sometimes harsh decisions have to be taken. That is the reason we have reduced the subsidies." सब्सिडी घटा दी और आप कहते हैं कि सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। इसलिए हमने डीजल की कीमत बढ़ा दी, यह आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर का बयान है। "We have increased the price of diesel. The families are affected by the burden of diesel which affects the entire economy of the country." सर, यह आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर का बयान था। आप कह रहे हैं कि यह तो खाद्य पदार्थों पर बहस है। उस वक्त आपके खाद्य मंत्री हिमाचल प्रदेश के शांता कुमार जी थे। शांता कुमार जी, जब पार्लियामेंट के अंदर बहस हुई, तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन की देश की जनता है - बिलो पॉवर्टी लाइन और गरीब लोग, हमारे देश में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 1.1 बिलियन लोग एक डॉलर से कम कमाते हैं। एक बिलियन, 100 करोड़ से ज्यादा लोग एक डॉलर से ज्यादा नहीं कमा पाते, यह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और दो अरब से ज्यादा लोग, 2.7 बिलियन, 270 करोड़ लोग 2 डॉलर से ज्यादा नहीं कमा पाते, यह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। हमारे यहां 1974 में below poverty line लोग 54 परसेंट थे, Economic Survey के मुताबिक आज वे घट कर 27 परसेंट लोग हैं। आधे हो गए है। गुरबत सिर्फ हिन्दुस्तान के अन्दर नहीं है। यह कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया इससे जूझ रही है।

सर, शान्ता कुमार जी ने, उस वक्त की सरकार ने 50 परसेंट सब्सिडी घटा दी और यह 50 परसेंट सब्सिडी किसी अमीर आदमी की नहीं घटाई। वे लोग, जो below poverty line रह रहे हैं, जिनकी चर्चा आज पार्लियामेंट के अन्दर हो रही है, जिनको आज हमारी सरकार 5 रुपए और 2 रुपए के अन्दर गेहूं और चावल दे रही है, आपकी सरकार ने उनकी 50 फीसदी सब्सिडी घटा दी। जब पार्लियामेंट के अन्दर यह हंगामा हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो शान्ता कुमार जी ने पार्लियामेंट के अंदर क्या कहा, वह मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): No, no. ...*(Interruptions)*... No running commentry please. ...*(Interruptions)*...

श्री राशिद अल्वी : आप सुनते रहिए, मैं आपको सब सुना दूंगा। ...(**व्यवधान**)... मैं आपको सब सुनाऊंगा, मैं सुनाने के लिए खड़ा हुआ हूं, आप सुनते रहिए।

"The issue price for the population below poverty line will be fifty per cent of the economic cost." आज economic cost करीब-करीब 18-19 रुपए है। वे कहते हैं कि जो economic cost होगी, हम उसका सिर्फ 50 परसेंट सब्सिडी देंगे, इससे ज्यादा सब्सिडी नहीं देंगे। जो लोग below poverty line से ऊपर हैं, APL हैं, हालांकि आज तक APL define नहीं हुआ है, APL, जो BPL से ऊंचा है और टाटा और बिरला तक APL के अन्दर

आते हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा, "I increased ten per cent in the rest 90 per cent." यानी 100 परसेंट कर दिया। सारी सब्सिडी खत्म कर दी। BPL की सब्सिडी 50 परसेंट कर दी और APL की total 100 per cent खत्म कर दी। यह मैं एनडीए के जमाने की सरकार की बात मैं कह रहा हूं। इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि नया सिस्टम लागू होना चाहिए। उस वक्त की सरकार ने नया सिस्टम लागू किया। He said that Minimum Support Price and Central Issue Price should be definitely linked to each other. Support price तो बढ़ता चला जाता है। 10 साल से support price लगातार बढ़ रहा है। यह हर साल बढ़ता है, लेकिन issue price नहीं बढ़ता है। उस वक्त की सरकार ने कहा कि नहीं, issue price के साथ ही support price बढ़ना चाहिए। अगर issue price बढ़ेगा, तो support price भी बढ़ेगा। कितना दर्द है आपके दिलों में गरीब आदमी के लिए! मैं तो यह speech सुन कर हैरत में रह गया कि एनडीए की सरकार के लोगों में कितनी तकलीफ थी।

सर, आज इस देश के अन्दर पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है, वह unprecedented है। ऐसा कभी नहीं हुआ, इतनी कीमत कभी नहीं बढ़ी। 150 डॉलर तक पेट्रोल की कीमत पहुंची। दुनिया के अंदर global GDP पेट्रोल की वजह से पिछले साल 0.5 परसेंट कम हुई। Global GDP के 0.5 परसेंट का मतलब है 255 बिलियन डॉलर। सर, 10 डॉलर के बढ़ने से करीब-करीब 150 बिलियन डॉलर का फायदा उन countries को होता है, जो पेट्रोल produce करते हैं। लेकिन हमारे यहां तो पेट्रोल 147 तक पहुंचा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ीं; मिट्टी का तेल, ये सारी कीमतें बढ़ीं। सर, पिछले दो साल से में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ने से हमारी क्रॉप के ऊपर भी फर्क पड़ा है। पिछले दो साल का वक्त हमारे देश के लिए मुश्किल वक्त रहा है। सर, मैं यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। 20 अक्टूबर, 2008 में, ठीक इलैक्शन से पहले हमार प्राइम मिनिस्टर ने इसी हाउस के अन्दर यह बात कही थी। सर हमारी ईमानदारी की तारीफ करनी चाहिए कि अप्रैल, 2009 में चुनाव होने वाले थे, लेकिन छः महीने पहले ही प्रधान मंत्री ने इसी सदन में यह कहा। मेरे पास ...(**समय की घंटी**)... सर मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा।

सर, प्रधान मंत्री जी ने यह कहा कि दुनिया के हालात खराब हैं, रिसैशन बढ़ रहा है और उसके असरात हिन्दुस्तान की इकोनॉमी पर भी पड़ेंगे। हालांकि चुनाव से पहले यह भी कहा जा सकता था कि नहीं, हम हालात पर कंट्रोल करेंगे, लेकिन देश के प्रधान मंत्री ने छः महीने पहले ही देश को आगाह कर दिया कि बुरा वक्त आ सकता है और हमें उसके मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए।

(**श्री उपसभापति** पीठासीन हुए)

वक्त कम है। सर, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर एक माहौल पैदा कर रखा है कि महंगाई बढ़ने की जिम्मेदारी सैंट्रल गवर्नमेंट की है और सैंट्रल गवर्नमेंट की वजह से ही महंगाई बढ़ रही है। क्या स्टेट गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या काला-बाजारों को सैंट्रल गवर्नमेंट पकड़ेगी? मैं यहां सरकार से कहना चाहूंगा कि सैंटर-स्टेट रिलेशनशिप का कमिशन तो बना है, लेकिन हमें सैंटर-स्टेट रिलेशनशिप के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा और अगर जरूरत हो तो कॉंस्टीट्यूशन को अमैंड भी करना पड़ेगा।

सर, Eleventh Five Year Plan के अन्दर स्टेट की जिम्मेदारी ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं दो मिनट और लूंगा। पीडीएस और फेयर प्राइज़ शॉप को लेकर सैंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वह गेहूं, चावल और तमाम खाद्य पदार्थ स्टेट तक पहुंचाएगा और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वह बीपीएल को आईडेंटिफाई करेगा, राशन कार्ड बनाएगा और राशन डिस्ट्रिब्यूट करेगा।

सर, स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में Eleventh Five Year Plan कहता है, "PDS seems to have failed in serving the second objective of making foorgrains available to the poor." स्टेट गवर्नमेंट्स नाकाम हो गई हैं। वे गरीब आदमी तक खाद्य पदार्थ नहीं पहुंचा पा रही हैं। सर, यह डाटा पेश करके मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा।

श्री उपसभापति : अल्वी साहब, वक्त नहीं है। Another two hon. Members have to participate, इसलिए अभी वक्त नहीं है।

श्री राशिद अल्वी : मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। सर, हम गरीब की बात करते हैं, सैंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को जो राइस का ऐलोकेशन किया, बिहार को जितना दिया गया, वह उसमें से केवल 62.9% ही उठवा पाया। गुजरात ने 95% उठाया और 5% छोड़ दिया, जिसे नहीं उठाया गया। झारखंड के अन्दर 93.6% उठाया गया। कर्नाटक के अन्दर 97% उठाया गया। वैस्ट बंगाल के अन्दर, वह मैडम यहां से चली गई हैं, वहां 88.7% उठाया गया, 12% नहीं उठाया गया।

एक अहम बात मैं हाउस को बताना चाहूंगा। जो मुनाफाखोर हैं, जिन्होंने गलत तरीके से अपने गोदाम भर रखे हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? मैं उसका डाटा बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। बिहार के अन्दर सिर्फ चार जगहों पर रेड डाली गई।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have to finish, please.

श्री राशिद अल्वी : सर, मैं खत्म कर रहा हूं ...(**व्यवधान**)... बिहार के अन्दर 4 raids हुईं और इन 4 raids में न तो एक भी आदमी पर मुकदमा चला और न ही एक भी आदमी को सजा हुई। गुजरात के अन्दर 21 हजार 281 raids हुईं और 74 लोगों पर मुकदमा चला लेकिन किसी को भी सजा नहीं हुई ...(**व्यवधान**)... कर्णाटक के अन्दर 881 raids हुईं ...(**व्यवधान**)... देखिए, रेत को निचोड़ कर पानी निकालना बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, बहुत दिनों से हम यह काम कर रहे हैं। हम इसकी लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसकी कीमतें कम होंगी।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Mr. Deputy Chairman, Sir, first of all, I would like to apologise to the hon. Members who have made their contributions on this important issue of 'price-rise' as I was physically not present to listen to them because the discussion is taking place in both the Houses. So, I had to remain present there, I will make a brief intervention and, of course, the reply would be given by the Minister Sharad Pawarji.

First of all, I would like to express gratitude to all the hon. Members who have participated and made their contributions on this important issue. Price issue is an issue which is, basically, not a political issue. It is, essentially, an economic issue. Of course, we have different perceptions and we look at it from different angles, but the ultimate objective of everyone, to whichever party he or she may belong to, is: how to redress the sufferings of the people, how to protect the vulnerable sections of the people from the adverse impact of the price-rise. That is underlying the debate, and I would like to start from that point of view that everybody is interested in finding the way, in finding the

mechanism, through which we can ensure that the people do not suffer. It is nobody's claim that prices are not rising or people are not suffering when the essential commodities reach beyond their capacity. But, at the same time, we shall have to keep in mind that this fundamental economic issue cannot be resolved merely by rhetoric. Any amount of words, any amount of expression of anger or sentiments does not alter the basic roots of the economy. If a commodity is in short supply of the demand, it would have its impact. The demand can be met by filling in the gap between the availability and the demand by import. But if the international prices of the commodity are high then you cannot reduce the price. What you can, at the maximum, do is, if you have enough money, you can reduce the adverse impact of the high prices by providing a subsidy.

But the prices cannot be reduced. You can ameliorate the sufferings by providing subsidy, as has been done in the case of petroleum products. We are providing subsidy to the tune of Rs.87,000 crores to 1,03,000 crores on almost all the petroleum products, petrol, diesel, LPG and kerosene. I don't know whether in any part of the world one litre of kerosene is subsidised by Rs.31. It is not done in any of our neighbouring countries. I checked. But that does not mean, when you are selling kerosene at Rs.8 plus, the price of kerosene is Rs.8. The price of kerosene is Rs.31 plus Rs.8 in Indian costs. So, keeping that in view, we shall have to take note of what steps should be taken and what steps have been taken.

Sir, somebody has asked: What is the relevance of MSP? Most respectfully, I would like to submit that there is some relevance of MSP. When we increase the Minimum Support Price and procure 34 per cent of the total production, we set the benchmark of the market value. Now, what has been the Minimum Support Price? Take the case of wheat. In 2005-06, the Minimum Support Price per quintal of wheat was Rs.700. In 2009-10, it has been increased to Rs.1,100 per quintal of wheat. Now, let us calculate the price. If we keep the procurement price at Rs.1,100 per quintal of wheat and add to that the local tax of 12.5 per cent, the cost of handling, the cost of transportation, etc., then, in terms of actual price, it will come to Rs.13.50 per kilogram.

Similarly, take the case of paddy. Now I provide the procurement price of paddy at Rs.1,050 per quintal, if I convert one quintal of paddy into rice, it will give me 62 to 63 kilograms of rice. Then, you add these two charges. Hon. Members are well informed that different political parties run different State Governments. One of the important debatable points on the GST is the purchase tax or the local tax. The purchase tax even on food items varies from 6 per cent to 12.5 per cent in almost every producing States. Taking into account the Minimum Support Price of Rs.1,050 per quintal of paddy that I provide, the price of rice will be Rs.19.40 per kilogram. That is the economic cost. Any amount of rhetoric can't reduce this cost. It will be there. The question is whether we can protect the

poorer sections, at least, or not through any mechanism. One of the effective mechanisms is effective Public Distribution System. We have the Targeted Public Distribution System. There is a debate going on. Somebody demands that there should be universal coverage by the Public Distribution System. Yes, it is ideal. Nobody is denying it. It is ideal if we can have universal coverage by the Public Distribution System of the 120 crore people of this country.

It is one thing in claiming or demanding and it is another thing in putting into practice. Even if I assume, as per the Planning Commission's assessment, 6.5 crores BPL families, are we in a position – I am not blaming anybody because I am part of the system – are we and the State Governments in a position, today, to serve the 6.5 crores families by providing rice at Rs. 6.50/-, wheat at Rs. 5.50/-, wheat at Rs, 3/- for the AAY? Have we been able to provide the subsidised edible oil which is available, which is on tap right now, at a subsidy of Rs. 15/- per kg.? I have the figure. I would not like to mention the name of the States. Only nine States have taken advantage of the scheme. The scheme is on tap; anybody can take it any day. To have an effective impression on the market by larger quantum of arrival, we have suggested that you sale 2 million tonnes of wheat and 1 million tonne of rice through the open market sale scheme so that it would have some impact on the market. Some of the States have taken that advantage and some others are taking.

The second point on which I would like to make a comment is one area which is not debatable, to my mind, where we shall have to find a solution collectively by putting our minds together. All of us have read in daily newspapers, as we are staying here, the difference between the wholesale market price and the retail price. It has appeared in the Economic Times, the Times of India and several Economic magazines. There is a huge difference. What does it mean? The cost of intermediation! If I take the *mandi* price and then, actually, at what level the farmers are getting the price, it is much less. Then how to avoid this intermediation? What mechanism can we evolve? What could be the effective instrumentality for it? The question is of demand and suppy. The fact of the matter is, even in the mid 1980s, when we had the Mission Mode Programme for pulses production, it did not materialise much. Again we are having another programme. There is a continuous programme. All the public sector enterprises STC, MMTC, NAFED, PEC have been suggested that you go on importing pulses continuously and 15 per cent of your loss would be met by the Government. It is a continuing scheme. Currently, we are providing a subsidy of Rs. 10 per kg on pulses. It can be distributed through the PDS. Some of the States have taken advantage of it and some others have not yet. So I have requested them to have it. The prices of pulses, edible oil and sugar are increasing substantially because of the gap in demand and supply. This is one reason. This year, sugar production is expected to be 160 lakh tonnes. Our demand, as you know, varies from 220 to 230 lakh tonnes.

So, there will be a shortfall of 70 lakh tonnes. This is not so this year alone. Even in the last year, it was at that level. Sometimes, suggestions come that we build up the buffer stock. You can have buffer stock to meet a temporary crisis. If we look at the sugar trend, in 2006-07, our production was 282 lakh tonnes, and our requirement was 191 lakh tonnes. That means, almost 90 lakh tonnes were surplus. In the next year, the production was 263 lakh tonnes and the requirement was 205 lakh tonnes. The gap was 58 lakh tonnes. During the year 2008-09, production fell sharply to 146 lakh tonnes, and the demand was 220 lakh tonnes. In the current year, 2009-10, the forecast is that production will be 160 lakh tonnes and the requirement is 430 lakh tonnes. Somebody has suggested that I put a blanket ban on exports. Then, what should I do with the surplus? What about the buffer stock? Under what carpet, will you keep the money which you will be investing on buffer stocks and on maintaining the carrying cost? How will you be able to reduce the economic cost? And, if you don't export, then, what will the farmers do? What they are doing right now, they will do so that if they don't get the prices, they will switch over to other crops. Therefore, these are not simplistic solutions. Now, we have put all these' items under OGL with zero duty. But between January and January, the international sugar prices have increased by 110 per cent; pulses prices increased by 70 per cent. Therefore, import also is not a very easy option. Had it been so, when we had put it in the OGL, the private traders would have imported and made money. If they had found that the imported price was cheaper than domestic price, then, they would have imported it. But they are also not doing so because international prices are high and the lending price will be more. Therefore, keeping that in view, we shall have to ensure how we can provide a mechanism so that we can help the more vulnerable sections of the society. The questions put are: Why are you not resorting to monetary policy? Why don't you withdraw the entire liquidity from the market? It is not that we have not done anything. In the latest Monetary Policy, by enhancing CRR to 75 basis points, we have withdrawn nearly Rs.36,000 crores from the market. But are we to compromise our growth with it? Are we to resort to too much tight money policy? You please look at the trend of the prices. If we look at the inflationary trend, from the beginning of 2008-09, till today, in 2008-09, we noticed that the international commodity prices started firming up. It reached as high as nearly 13 per cent. Then, the Reserve Bank came into the picture. They restricted the money supply. The CRR was increased. Liquidity was absorbed. Just at that moment, the international financial crisis came. In the latter part, we had the adverse impact, but the rest of the world had it earlier.

The world leaders met and they decided 'that we cannot allow this financial crisis to engulf the entire economy. The economy must be resurrected.' And to resurrect it, they injected trillions and trillions of dollars. So much money was injected in the system and that had its impact. It would have its effect. We are not insulated. On the energy, we have to depend on them, on the international suppliers. Even on two essential food items, edible oil to the extent of 40 per cent and pulses to the

extent of 15 per cent, just now I have given you the international price trend on these items, we have to depend on them. Therefore, these had its adverse impact on our price level also. But, that does not mean that we have not done anything and we have left everything to take its own course of action. We have taken a series of steps. Some of the steps have been suggested. That is why I am mentioning it. We reduced the import duties to zero level for rice, wheat, pulses, edible oils, maize, butter and ghee; reduced the import duties on refined and hydrogenated oils and vegetable oils to 7.5 per cent; allowed the import of the raw sugar at zero duty under OGL; allowed the import of white and refined sugar by STC, MMTC, PEC and NAFED up to one million tonnes at zero duty. In addition to that, certain administrative steps were also taken. A suggestion was made that why don't you put a ban on the forward trading of certain essential commodities. Yes, it has been put; and certain essential items have been put on ban in the forward market. Futures trading on rice, two types of pulses, urad and tur were suspended by the Forward Market Commission in the year 2007-08 and it is still continuing. Futures trading in sugar has also been suspended with effect from May 2009. Therefore, these administrative measures are taken to help the more vulnerable sections of the society through PDS because that is the only instrument available to us. Through these PDS, what you have suggested is the two schemes. One is the subsidised edible oil and another is the subsidised pulses. These two items would be distributed to the PDS card holders in the small package; Rs.15 subsidy per kilogram of edible oil and Rs.10 subsidy per kilogram of pulses. Eight-nine States have taken advantage of the scheme. But, we have requested all other States also to take advantage of that. Also to have a depression on the market, to augment the supply in the open market, two million tonnes of wheat and one million tonne of rice have been allocated to the States that you distribute it not to the BPL families but to others at the MSPD. Some of the States have taken advantage of it, and in order to ensure that the big consumers like flour mills and others do not intervene in the market, additional one million tonne has been allocated to them. Therefore, keeping these in view, it was decided in the Chief Ministers' Conference, which was convened by the Prime Minister, that a small group should work out and their mandate is very clear as I have mentioned.

Here the hon. Members who are experienced and knowledgeable in this area can also make their suggestions how to reduce this intermediation cost from the firm to the kitchen, from wholesale market to the retail market because huge margins are being appropriated by them. They can suggest the measures which can be taken in this regard. The hoarding and all those detailed figures the Agriculture Minister will deal with it, I am not touching them. Those are temporary measures but there must be a permanent economic solution, a mechanism through which this cost of intermediation can be reduced. Finally, Mr. Deputy Chairman, Sir, a question has been raised why we are not fulfilling our commitment in respect of the enactment of Food Security Act. We are committed to enact the

Food Security Act and we are going to do so, but, surely, the year, the calendar year which we have completed just now, it was not possible in it. I remember the debates in this House and that House on drought. In that drought situation, when somebody suggested that, Sir, there will be street riots, food riots, it was not possible to undertake the responsibility of providing food to a particular section of the society at a guaranteed price and that is the legal right, therefore, it was thought at an appropriate time and which I do feel we are reaching that stage. So, it would be possible for us to enact the Food Security Act. But legal entitlement is one thing, to create the conducive condition to fulfil that legal entitlement, to back up that legal entitlement, the country must be self-sufficient in food production and there comes the question of massive investment in agriculture, 4 per cent sustainable growth in agricultural sector and its allied sectors. These are, of course, the larger which the hon. Members will get the opportunity of participating and making their views. I am not taking the statistical advantage because this time in the last year, WPI was negative, we did not claim any credit for that. From November to June, WPI was negative and that is why when base is negative even with some rise, it becomes very high positive figure. That is statistical figure, but that is not consolation. Even CPI did not, that was reasonably high throughout the year, that is why I am not taking advantage of that. But the steps which we have taken to improve the supply-demand management, the steps which we have taken through monetary mechanism that whichever excess liquidity would be mopped up and it has been mopped up by enhancing the CRR by 0.75 per cent, to the extent of 36,000 crores of rupees, I do feel it would have some moderating impact on the inflation. Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir.

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Can I seek one clarification?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is only intervening. ...*(Interruptions)*... No, no, it will be very difficult. ...*(Interruptions)*... The reply is still pending.

SHRI SITARAM YECHURY: I am not on reply, Sir. I am seeking clarification on what the Finance Minister has said. ...*(Interruptions)*... it will help the whole House, all of us. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE; Excuse me. On the eve of Budget, I would not like to make any observations, please remember that. ...*(Interruptions)*... It is not the practice that the Finance Minister speaks before the Budget, but as the Leader of the Opposition, and some other Opposition Members wanted me to speak, I volunteered. But I would not indulge in any clarifications or other things.

SHRI SITARAM YECHURY: The spirit is taken. ...*(Interruptions)*...

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, I recall an earlier occasion when we were discussing precisely the hike in prices of commodities, and I had to

get up in a similar occasion immediately following upon Pranabda's intervention now. The point made at that time was reiterated by Pranabda today that it is essentially a matter of mismatch between demand and supply.

The more important question is, what causes this mismatch between demand and supply? Sir, since October, 2009, this is the fifth time I am getting up in this House to make the point that this mismatch is essentially caused by what is called the *aam aadmi* economics and a number of schemes including the flagship schemes which result in a lot of money being pumped into the hands where production gets discouraged and demand gets supported. I made that point on three successive occasions. This has now support of the President of India herself who, in her Address to the Joint Session, admitted that the increase in commodities' prices had a link with the policies supporting the *aam aadmi* that her Government had been following.

Sir, I do not know what position the Agriculture Minister will take in the House, but in Maharashtra he has been going round saying that the price increase is largely due to the fact that a lot of money is going into the hands of the people. In fact, I have seen him, heard him, asking the large gathering, "What is the amount of money you received under the Sixth Pay Commission? What is the money your family received under the NREGA?", etc. Therefore, the one point that has become clear is the link between the *aam aadmi* economics and the increase in prices, and since it is established. The question is, now what do we do about it? Sir, I would like to make it clear that in my opinion, the drought has nothing to do with it. The Government had abundant stocks of foodgrains in the country and the Prime Minister had also mentioned that this year there should be no cause for any concern. The calculations probably went wrong and we have a situation which is relatively difficult.

The second thing that has to be questioned is, are we prepared for a repetition of the vagaries of climate for the next year? This year, we had a drought. Next year, it might be extreme inundation, another freak of the nature. Is the Government now prepared to face the situation where the Government will be able to keep the production of agricultural crops more or less intact? Sir, his claim that he has increased the statutory minimum prices is no justification. In Maharashtra alone, in the last 25 years, under the Congress regime, 35 of my colleagues have been shot down by the police for the sin and crime of asking the remunerative prices and a legitimate statutory minimum price. If he is now justifying the statutory minimum prices, he is coming 25 years too late. Today, what is required by the farmers is not so much SMP as a fairly liberal exit policy and a fairly liberal petroleum policy which will permit him to earn income from the production of ethanol and other bio-fuels.

The point that I would like to make is, if we are going to continue with the Gendarmary methods of using the *danda* and thinking that if the State Governments carry out raids, etc., then we

will not have the problem of increased prices, etc., is basically incorrect. Even Dr. Amartya Sen, the Nobel laureate made it very clear that the famine situation can be adequately faced if we have free communication and free transport systems. Sir, we have been following the Gendarmary method far too often. For example, when we had the licence-raj, quota-raj, industrial development did not take place. It is only when we turned in the opposite direction that we had the growth that we are witnessing today.

We are adopting a similar method by following anti-poaching approach for protecting our wildlife. It is not happening. Anti-poaching laws do not protect tigers, the tiger population is continuously coming down. Rather than going to the Gendarmry methods, I would suggest that we should think of an alternative system in which the CACP, FCI, PDS, and the APMC kind of vicious circle be completely broken and we have a system where the markets will be open, transparent and without any restrictions of time and space.

We will have a system where the markets will be open, transparent and without any restrictions of time and space. If that happens, I think that would be the kind of system which would ensure reasonable market prices. The Finance Minister asked a question: why is it that there is a difference between the prices that the customers pay and the prices that the farmers receive? Sir, on the basis of the experience that I have, I would say that the difference between the consumer's prices and farmer's prices are directly linked with the differential in the income of India and Bharat. It has nothing to do at all with the intermediary's profit. This is wrong economics which has been disproved over the last 25 years. If you want a solution for the present problem, stop restricting, stop intervening, don't import, don't export because there is only short term knee jerk reaction which will ultimately make the problem worse and worse. I would say that the policy that we really started from 1990s of opening up are going to be more useful for bringing down the prices and inflation and any other measure of carrying out the kind of activities we carried out under the Essential Commodities Act will actually worsen the situation and make the agricultural progress even slower than it has been up to now.

SHRI M. RAMA JOIS (Karnataka): Sir, price rise is a very serious problem adversely affecting the whole nation. But this has not happened at once. It is the cumulative effect of wrong policies followed over the years. If I start from the beginning referring to the Directive Principle of State Policy contained in article 48- Organisation of agriculture and animal husbandry, "The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle." In fact, from the beginning this article has not been properly implemented. It is a matter of common knowledge that India's main occupation has been agriculture. It is called Krishi Pradhan Desh. But, unfortunately, the importance that should have

been given to agriculture has not been given. So, many things have been done. But the amount of importance which had to be given to agriculture has not been given. This article was incorporated by the founding fathers of the constitution for improvement of agriculture and protection of cattle wealth. All the ancient smritis on Rajadharma provided that even unauthorisedly cultivation of land by the people should be condoned because food is of utmost importance. There were pastures - provision for reserving land for grazing called *Gomath* land. In every village, there was a prescription, in the earlier laws as well as in the subsequent laws, that there should be sufficient land reserved for *Gomaths* for the grazing of animal, *i.e.* cattle wealth. But, unfortunately, the *Gomaths* are disappearing. Earlier not even an inch of *Gomath* land could be granted to any other person, for any non-agricultural purpose but, unfortunately, this principle has not been followed and *Gomath* lands have been completely reduced in so many villages which has affected agriculture. I remember what Atal Bihari Vajpayee used to say in his speeches earlier. He used to say that our agricultural economy is based on बैल, घास और गोबर. We use the बैल for agricultural purpose and we feed them with grass and again we get गोबर. He used to say, तेल, ट्रैक्टर, रस, गोबर has become the present policy. तेल है ईरान में, ट्रैक्टर है हिन्दुस्तान में, धुंआ जाता है आसमान में। He used to say in a poetic language. Now, in fact, if we had protected the cattle wealth, there would have been no occasion for spending so much on chemical fertilizers. The subsidy given for chemical fertilizers is ten lakhs crores of rupees and for pesticides Rs. 30,700 crores.

Sir, ten years back, agricultural expenses was 7 per cent. Now, it has increased to 72 per cent. Recently, a Memorandum has been submitted to the hon. President on 31-1-2009 which has been signed by 8.35 crore persons. I give some figures from that. The share of cows in the GDP was 6.01 per cent, but, allocation in the Budget for cows is 0.115 per cent. The share of cows in agriculture is 27.2 per cent. But, the Budget allocation is 11.7 per cent. Even though we derive so much of income from cow, we are not investing sufficient funds for betterment of cattle wealth. We call cow as *Gomata*. There is a beautiful definition explaining this expression. When I say impose ban on cow slaughter. Some people ask me why only cow should not be slaughtered. There are also other animals which are being slaughtered. What is the difference between cow and others? But, there is a Sanskrit verse. It explains in three lines what is cow. It says, भुक्ता तृणानि शुष्कानि, cow eats grass पीत्वा तोयं जलाशयात् and it goes and drinks water in some tank दुग्धम् ददाति लोकेभ्यः but gives milk to entire humanity. Therefore, "गावो विश्वस्य मातरः" And, another important difference between cow and other animals is of all animals and humans it is *malmootra* of all animals and all human beings is *tyajya*, but only cow dung and cow urinals is treated as *pujya*. That is the difference. Even under Article 14, there is a reasonable classification. So, the cow stands on entirely reasonable classification when compared to other animals. Therefore, there is a directive under the Directive

Principle of State Policy under Article 48 that there should be a total ban on cow slaughter. Unfortunately, we take oath that we will abide by the Constitution. But, never implement it. That has a great adverse affect on our agriculture, because our entire agriculture is based upon cattle wealth.

Sir, as I said, 8,35,67,041 persons signed a Memorandum and presented the same to the hon. President on 31st January, 2010 demanding ban on cow slaughter. But, unfortunately there is no reference to this in the President's Address to both the Houses of Parliament. Had Article 48 been implemented, the nation would not have been facing food scarcity.

We should have made special agriculture zones. Mr. Deputy Chairman, Sir, you are very well aware that around Bengaluru how many resorts have come into existence. Sir, the Land Refrom Act, section 79, says that no agriculture land can be purchased by non-agriculturist. But, what is happening is that hundreds of acres of agricultural land has been converted into resorts which are meant for luxury for rich people. So, large tracts of land are not being used for agriculture purpose. Therefore, the need of the hour is, we must not only reserve land for pasture of cattle but also made special agricultural zone so that it can be used for agriculture only.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI M. RAMA JOIS: Then, Sir, there is exodus from villages. Now, what is happening is, for want of facilities, there is exodus from villages and the lands are becoming fallow as they are not being cultivated. We must improve the standard of living, health and all other things in villages so that villagers do not leave villages and come to towns. And, about so many resorts – I don't know how they have come into existence – which have come up in hundreds of acres and only a few rich people go there and spent their weekend for whatever it is. I urge that this should be controlled and they should be reconverted into special agriculture zones.

Sir, Mahatma Gandhi said Grama Rajya. Now, number of *'Gramas'* are dwindling. As a result of we have to purchase everything in grams. That has become the position. So, unless we implement Article 48 in totality and impose a total ban on cow slaughter, food grains production cannot improve.

I have got figures. 2.5 crore cows are being slaughtered every year; forty to fifty lakhs cows are being exported to Bangladesh. In such a situation, how our agriculture can improve. And, without improvement in agriculture, we cannot have more production; and, without more production, we cannot have lower prices.

प्रो. अलका क्षत्रिय (गुजरात) : धन्यवाद उपसभापति महोदय। आज सदन में महंगाई जैसे आम जनता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और इस चर्चा में इसके समाधान और उपायों पर आम राय बने, यह बहुत जरूरी है। महंगाई जैसा विषय आम वर्ग और खास वर्ग, सभी से जुड़ा हुआ है। मैं अपने विपक्ष के मित्रों से

सहमत हूं कि महंगाई बढ़ी है और यह चिन्ता का विषय है, हमारे लिए भी और सरकार के लिए भी। सरकार इसके लिए चिन्तित है और जनता को इससे निजात दिलाने के लिए कारगर उपाय भी कर रही है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी इस विषय को गम्भीरता से लिया है और वे लगातार महंगाई घटाने के लिए कारगर कदम उठा रहे हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि धीरे-धीरे महंगाई कम होती जा रही है। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना होगा कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। हम सब जनता के प्रति जवाबदेह हैं। हम सभी जन-प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रति जवाबदेह होने की वजह से हम इससे बच नहीं सकते। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि भला कोई भी सरकार यह क्यों चाहेगी कि महंगाई बढ़े, जनता इस समस्या से त्रस्त हो। सरकार तो हमेशा जनता की भलाई के लिए ही कार्य कर रही है, लेकिन महंगाई बढ़ने के जो कारण हैं, वे यह हैं कि विगत 2-3 वर्षों से आवश्यक सामग्रियों का उत्पादन कम होता जा रहा है। इसके लिए कई कारण जवाबदेह हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उत्पादन कम होता जा रहा है, क्योंकि कहीं सूखा पड़ रहा है, तो कहीं बाढ़ आ रही है। इस वजह से उत्पादन में काफी कमी आ रही है। इतना ही नहीं, हमारी खेती भी वर्षा पर निर्भर है और यह भी इसके लिए जिम्मेदार है। उत्पादित वस्तुओं की कीमत का जो असंतुलन बना हुआ है यानी wholesale और retail price में जो असंतुलन है, वह भी इसके लिए जिम्मेदार है। एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि आज किसान भाई पैदावार के लिए जिस वस्तु, जिस अनाज या जिस सामग्री को चुनते हैं, उसमें भी काफी बदलाव आ गया है। आज किसान भाई चाहते हैं कि उनको अपने उत्पादन का जल्द-से-जल्द और ज्यादा मूल्य मिले। इस वजह से वे cash crops की तरफ ज्यादा मुड़ गए हैं। मैं जहां से आती हूं, उस गुजरात की बात करूं, तो मेरे एरिया में अब किसान भाई ज्यादातर जीरा, अरण्डी, कपास और फूलों की खेती की तरफ मुड़ गए हैं। इस वजह से पैदावार कम होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सीमित आपूर्ति हो रही है, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। साथ ही आढ़तियों द्वारा की जाने वाली जमाखोरी भी एक प्रमुख कारण है। कालाबाजारी और जमाखोरी, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है और केन्द्र सरकार काफी गम्भीरता से इसको कम करने का प्रयास कर रही है। जब हम केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी की बात करते हैं, तो मैं यह भी पूछना चाहूंगी कि क्या राज्य सरकारों की इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या राज्य सरकारें इससे बच सकती हैं? आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी बढ़ी है और इसी वजह से अगर केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से अपील करती है कि आप मुनाफाखोरी और कालाबाजारी रोकें, आप अवैध स्टॉक पर छापामारी करें, तो इसमें वह क्या गलत कर रही है? मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि यह कितना कारगर उपाय है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जब छापामारी करके चीनी का बड़ा स्टॉक पकड़ा, तो इसकी वजह से उसी दिन चीनी की कीमत एक रुपए कम हो गई, ऐसी मीडिया की रिपोर्ट आई है। मुझे लगता है कि यह कारगर उपाय है। इसी बात को ध्यान में रख कर अगर केन्द्र सरकार यह कहती है कि राज्यों को भी सहयोग देना चाहिए, उनका भी सकारात्मक रुख होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि केन्द्र सरकार ने कोई गलत बात नहीं कही है।

जो राज्य इस बात पर हंगामा कर रहे हैं कि केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी हम पर थोप रही है और स्वयं बच रही है, वह गलत कर रहे हैं। हकीकत में ऐसा नहीं है क्योंकि केन्द्र सरकार पूरी तरह से गंभीर है, लेकिन केन्द्र सरकार यह बात भी कह रही है कि राज्यों को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आखिर केन्द्र और केन्द्र सरकार है क्या? भारत राज्यों का संघ है, इस वजह से केन्द्र नीतियों का निर्धारण करता है, लेकिन इस बात से भी कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि उन नीतियों को निर्धारित करने में राज्य सरकारों की भी अहम भूमिका होती है। अगर राज्यों को उनकी भूमिका अदा करने के लिए

कहा जाए, तो हम लोग यह नहीं कह सकते कि उन पर यह जिम्मेदारी थोपी गई है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूं। मान लीजिए एक गाड़ी को चलाना है, जिसके चार पहिए और एक इंजिन है। अगर चारों पहिए अलग-अलग तरह से चलेंगे तो गाड़ी नहीं चल पाएगी, ऐसे में आप इसका दोष किस पर डालेंगे? इसमें इंजिन का दोष है या पहियों का दोष है? यह मिलीजुली साझी सरकार है और हम लोगों को मिल कर इस बात को निभाना होगा।

कुछ सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई भी है, जैसे दिल्ली की सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के स्टॉल लगाए, जिसकी वजह से यहां पर खाद्य सामग्रियों के दाम घटे हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र की सरकार ने भी दालों के स्टॉल लगाए, जिसकी वजह से वहां कीमतें कम हुई हैं। बाकी सरकारों को भी इस तरह का कदम उठाना चाहिए। माननीय प्रणव मुखर्जी जी ने जो बात कही थी, उसे मैं दोहराना नहीं चाहती हूं। उन्होंने साफ कहा कि कुछ सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है, लेकिन बाकी सरकारें सहयोग नहीं दे रही हैं। बाकी सरकारों को भी इस संबंध में अपनी जवाबदेही पूरी करनी चाहिए। वे भी प्रजा के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी रखती हैं।

महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि क्या राज्य सरकारें उन राज्यों की जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हैं? क्या वहां पर किसान नहीं रहते हैं? क्या वहां पर उपभोक्ता नहीं रहते हैं? किसानों को अपनी पैदावार का उचित दाम मिले, उचित सहायता मिले, उचित सलाह मिले, उचित संसाधन मुहैया करवाए जाएं, क्या इसके लिए राज्यों की कोई जवाबदेही नहीं है? कीमतों पर नियंत्रण रखना और उपभोक्ताओं को समय पर सामग्री उपलब्ध कराना राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है, इसके लिए केवल केन्द्र पर कोई दोषारोपण का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। यह साझी सरकार है और हम सब लोगों को मिलजुल कर इस पर कार्य करना होगा।

मैं यहां पर बैठे हुए हमारे वाम मोर्चा के भाइयों को कुछ याद दिलाना चाहती हूं। आपको ध्यान होगा कि तीन साल पहले आपने एक रैली निकाली थी जिसमें आदिवासी भाइयों ने अपनी मांग रखते हुए बड़ी तोड़-फोड़ कर दी थी। अगर हम इस पर गंभीर नहीं हुए तो फिर से लोग उसी तरफ मुड़ेंगे। ऐसे में वे राज्य सरकारों को भी नहीं बख्शेंगे, हमें इस बात को भी समझना होगा।

केन्द्र सरकार इस समस्या से किस तरह से जूझ रही है, वक्त की कमी को देखते हुए मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगी। श्री प्रणव मुखर्जी जी ने यह पहले ही बताया है कि इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं। राज्यों को ज्यादा खाद्य सामग्री आबंटित करने की केन्द्र ने जो अपील की है, उसे राज्यों को भी गंभीरता से लेना चाहिए और अपनी जवाबदेही को पूरा करना चाहिए। भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी उन्होंने बताया है कि इसके लिए खाद्य सुरक्षा विधेयक तैयार किया जा रहा है।

भंडारण एक प्रमुख समस्या है। उस समस्या को सुलझाने के लिए एवं भंडारण सुविधा के विकास के लिए केन्द्र सरकार ने एक अलग विधेयक तैयार किया है, जिसको लाने की तैयारी भी सरकार के द्वारा की जा रही है। इसी तरह से सरकार घरेलू स्तर पर खाद्यान्न बढ़ाने के प्रयास कर रही है, साथ ही साथ आयात के जरिए भी घरेलू बाजार में विभिन्न खाद्यान्नों की उपलब्धता को बढ़ाने की कार्यवाही की जा रही है। मैं मानती हूं कि सरकार के इन प्रयासों की हम सभी को सराहना करनी चाहिए। किसानों को सस्ता कर्ज मिल सके, इस तरह की योजना भी

सरकार द्वारा बनाई जा रही है। राज्य सरकारों को भी उसका लाभ उठाकर किसानों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे अनाज का उत्पादन बढ़े और पैदावार बढ़ने से अनाज की कमी पूरी हो सके।

आखिर में मैं आपको यही कहना चाहती हूं कि महंगाई एक प्रमुख चुनौती है और मिलजुल कर हमें इस चुनौती का सामना करना होगा। यह केवल केन्द्र सरकार का प्रश्न नहीं है और न ही यह केवल राज्य सरकार का मसला है। यह साझी जिम्मेदारी है और इसका हल भी हमें साझे तरीके से ही निकालना होगा। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि विपक्ष भी इस बात पर सहमत होगा और इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार का भरपूर सहयोग करेगा। आने वाले समय में हम इस देश की खाद्य समस्या का समाधान निकाल पाएंगे, इसी आशा के साथ मैं अपना वक्तव्य पूरा करती हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत आभार।

श्री अवनि राय (पश्चिमी बंगाल) : सर, यह विषय बहुत गम्भीर है। यहां सभी ने इसे गम्भीर विषय बताया है तथा यह भी बताया है कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन, जिस तरह से बात चली है, उसमें मुझे राजनीति दिखाई दे रही है।

सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जनता इसको भुगत रही है। देश की जनता को महंगाई के चलते बहुत असुविधा हो रही है और उसमें सरकार बिल्कुल कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। सब कह रहे हैं कि वह सरकार चाहे राज्य की सरकार हो या केन्द्र की सरकार हो, सब को मिल कर इसमें काम करना चाहिए। यह काम राजनीति से ऊपर उठ कर होना चाहिए। मैं भी यह मानता हूं कि यह एक ऐसी समस्या है जिसको हल करने के लिए राजनीति से ऊपर उठकर ही काम करना चाहिए। लेकिन, हमारे बहुत सारे साथियों ने इसके पक्ष में भी बातें रखी हैं। महंगाई हुई, देश-भर में हुई, दुनिया-भर में हुई और इनके जमाने में हुई, उनके जमाने में हुई, आदि बहुत सारी बातें उन्होंने रखीं। उससे यह जाहिर होता है कि यहां पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो महंगाई के पक्ष में हैं। दुर्भाग्य यह है कि देश की जनता रो रही है और यहां महंगाई के पक्ष में बात की जा रही है। यह अफसोस की बात है।

इस पर बहुत बार चर्चा हुई। इसी कारण से इस बार सदन में जो बात की गई थी कि यह चर्चा 167 के तहत लाई जाएगी। अगर सरकार ने इसे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे उपाय अपनाए हैं, जो यहां पर बताए जा रहे हैं, तो उसे किस बात का डर था? अगर यह चर्चा 167 के तहत हो जाती है तो उसे डर किस बात का था? जब डरने की कोई बात ही नहीं थी तो आप 167 के तहत इसको discuss कर सकते थे और सदन की दो दिनों की कार्रवाई जो रुक गई, वह कार्रवाई पूरी हो सकती थी। लेकिन, आप डरे हुए हैं। आपको मालूम है कि PDS की जो व्यवस्था आपने की, वह ठीक नहीं है। आपकी procurement policy ठीक नहीं है। आपने MNC वालों को और retail sector वालों को store करने की जगह दे दी, जिसके कारण आज ऐसी हालत है। हमारे संतुलित आहार या पौष्टिक आहार की जो सूचियां हैं, उन पर किसी की नजर है ही नहीं। आज हालत यह है कि गरीब जनता, मेहनतकश जनता मर रही है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप दाल रोटी नहीं दे पा रहे हैं। अगर गरीब किसान और मजदूर के बच्चों को दाल रोटी नहीं मिलेगी तो दो दिन बाद या दो सालों के बाद उनकी ऐसी हालत होगी कि पौष्टिक आहार न मिलने के कारण, संतुलित आहार न मिलने के कारण उनमें malnutrition होगा, इससे हमारे देश में सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बच्चों के साथ-साथ न जाने कितने जवान भी मरेंगे। कुछ दिन पहले उड़ीसा राज्य में ऐसा हुआ।

उड़ीसा में बोलांगीर और कालाहांडी में ऐसी घटना घटती है, लेकिन हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। 50 आदमी मरें उससे हमें कोई खौफ नहीं है। उसके बारे में हमने कभी कुछ बोला ही नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरा कहना है कि इस PDS की व्यवस्था को आप ठीक ढंग से लागू करें। जहां पर जमीन है, जमीन को लेकर छेड़खानी न हो। आप procurement policy को ठीक से अपनाएं तथा black market और जमाखोरी की जो बात कही गई है उसके ऊपर अगर आप कहीं पर रोक लगा सकते हैं, तो वह करके देखें। आप retail shops को जितना बढ़ावा देते जा रहे हैं और retail shops वाले इसको जितना स्टोर करते जा रहे हैं वहां पर अगर आप हमला न बोल सकें तो आपको इसमें दिक्कत आएगी। जहां तक चीनी की बात है तो जो soft drinks बनाने वाले हैं, उन्होंने कितनी चीनी को स्टोर करके रखा है, उसे देखा जाए। अगर यह सब आप नहीं देखेंगे तो आपका जो slogan है "Food for all" कि सबको खाना देंगे, यह slogan एक slogan ही होकर रह जाएगा।

मैं अंत में यही कहूंगा कि 'मजदूरों को दाल-रोटी जो दे न सके सरकार, उस सरकार को सत्ता में रहने का न हो कोई अधिकार'। ...(**व्यवधान**)... पुराना होने से क्या होगा? पुराना हो या नया हो, ...(**व्यवधान**)... तारिक साहब, आप जरा शरद पवार साहब को कहिए कि वह कम-से-कम पुराने लोगों को समझें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. P. Kannan; you have only five minutes.

SHRI P. KANNAN (Puducherry): Hon. Deputy Chairman Sir, I rise to say a few words on price rise.

Sir, a lot of things have been said. Of course, price rise in the country is very alarming. It is the concern of the whole nation, all parties, the Ruling as well as Opposition parties, and the people of this country. Nobody is shying away from the fact that price rise has to be checked immediately, vigorously and vehemently. Before going into the issue at hand, I think the whole House would agree with me when I say that the Central Government, under the stewardship of Shrimati Sonia Gandhi and the leadership of Dr. Manmohan Singh, is honest enough to admit that there is price rise, there is a crisis in the country, there is an issue in the country to be looked into and a solution to be found. The Government is honest enough. We are not shying away. We are not running away. We are not finding any false excuse. We are not shying away from the responsibility or saying that the problem is not there. It is very much there. But, as the hon. Finance Minister has said, we need to find a mechanism to check prices and find a way out of the sufferings of the people of the country. I have gathered from a few newspapers in Delhi that there is a vast difference between the *mandi* price and the retail price. It is very alarming. On the other hand, I do not understand why that great a price does not reach the farmers. Somebody in between takes away the money. It is happening in our country. At the same time, I would like to say to the Government that some sort of a mechanism, not only the PDS, but some special mechanism, has to be devised to find out why, when *mandi* price is so low, retail price is so high in our country. What is the actual problem? What is the reason behind it? Why don't we straightaway meet the problem and sort it out? Neither the farmers nor the people are benefited; people in between are highly profited and taking away the money of the people.

Sir, the hon. Prime Minister is not the Prime Minister of the UPA Government alone; he is the Prime Minister of the whole country. India is the only country in the whole world that has withstood the economic recession, the financial recession, the great global challenge, and Dr. Manmohan Singh, the great economist and strategist and honest man that he is, has made the country stand up to the challenge when great countries like America, Russia, France and other European countries were terribly shaken up.

Many banks collapsed and several people lost their deposits in the past. But not even a single pie of people of this country is unprotected. This country was kept safe. The global recession did attack India but because of Soniaji, because of Manmohan Singhji and because of our UPA Government nothing affected India much. This is history. It is the fortune of this country that our Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, is there. Otherwise, I tell you ...*(Interruptions)*...

श्री रवि शंकर प्रसाद : उपसभापति महोदय, चर्चा महंगाई पर हो रही है, स्तुतिगान पर नहीं हो रही है। चर्चा महंगाई पर हो रही है।

SHRI P. KANNAN: I assure you ...*(Interruptions)*... Ravi Shankarji, I assure you. ...*(Interruptions)*... I understand that sufferings are there. People are suffering because of price rise; people are suffering because of various things. As a Congressman, I honestly admit it as is admitted by our hon. Prime Minister. He has not said, 'No'. He honestly said, 'Yes', I do share it. He said that. That sort of political honesty is with him. What I am saying now is that the same Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, is going to check the price rise of essential commodities in the very few weeks or months. It is going to happen because the strategy has been made. He has completely, quietly and patiently listened to both Houses, Rajya Sabha and Lok Sabha. Sir, one learned Member of BJP, I believe, has said about cow – how cow eats; what it eats and how it yields milk. I can say to our learned Member that ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. KANNAN: Our Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, is a typical Hindu-Indian cow. I don't say 'Hindu cow', but 'typical Indian cow'. He absorbs all shocks; he absorbs all bad things; he absorbs all bad effects; he absorbs all bad global impacts, but he delivers good things because he has love for people. He delivers the good things for the whole country. The whole world is looking at this country, this great country, how this developing country is marching ahead. This is not a matter of shame for the Government. This is a challenge for the Government and this Government would be victorious in this at the end.

श्री किशोर कुमार मोहन्ती (उड़ीसा) : उपसभापति महोदय, आज जिस मुद्दे पर इस सदन में चर्चा हो रही है, वह निश्चित तौर पर एक आम आदमी का मुद्दा है। आम आदमी का मुद्दा लेकर आज की यह यू.पी.ए. सरकार बनी थी। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार) : उपसभापति जी, मेरा नाम नहीं है क्या?

श्री उपसभापति : आपका नाम है। What can I do? सबका नाम है, but it has to be in order.

श्री राजनीति प्रसाद: पांच घंटे से बैठे हैं बोलने के लिए।

श्री उपसभापति : उसके लिए तो सब बैठे हैं, क्या करें। जिनका नाम है, उनको बैठना पड़ेगा।

श्री किशोर कुमार मोहन्ती : लेकिन उस आदमी को यू.पी.ए. की सरकार भूल गई है और जब आम आदमी इस महंगाई से तड़प रहा है, तब यू.पी.ए. की सरकार और उसके सभी घटक यहां पर कह रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है। सर, मुझे एक कहावत याद आती है कि *इनको महंगाई नज़र नहीं आ रही। इनको बाजार जाना चाहिए, जहां पर एक आम आदमी सामान खरीद रहा है, वहां पर इनको सामान खरीदना चाहिए, तब जाकर इनको पता चलेगा कि महंगाई कहां पर है। अगर इनको महंगाई नहीं दिख रही है तो उसके लिए सदन या हिन्दुस्तान का आम आदमी कुसूरवार नहीं है। अगर कोई कुसूरवार है, तो इनका administration है, इनके मंत्रिगण हैं, जो आज यहां पर देश की सत्ता संभाले हुए हैं। यह जरूरी है कि जो मूल्य वृद्धि हुई है, उसके ऊपर वे काबू रखें। उस पर काबू न रखकर अगर ये कहेंगे कि आज कोई inflation rate नहीं बढ़ा है, price hike नहीं हो रहा है, तो यह गलत बात है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जब कभी भी मूल्य वृद्धि होती है, तो केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के ऊपर दोष लाद देती है। जब केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाती है, तो इस तरह के तरीके अपनाती है। तब स्टेट की जितनी गवर्नमेंट्स हैं, जो non-Congress governments हैं, उनके ऊपर दोष लादकर वह अपना बचाव करती है। अभी कुछ सदस्य यहां पर कह रहे थे कि हमारी जितनी भी non-Congres governments हैं, वहां प्रधान मंत्री जी के आदेश पर सबसे ज्यादा raids हुई। रेट न बढ़ें, इस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा raids जहां पर non-Congress goverments हैं, वहां हुईं, जब कि कांग्रेस शासित राज्यों में इतनी ज्यादा raids नहीं हुईं और न ही कोई action हुआ। चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आसाम हो, ये सब राज्य, कांग्रेस शासित राज्य हैं, यहां पर भी महंगाई है, यहां पर भी महंगाई आम आदमी की कमर को तोड़ रही है। उस आम आदमी से अगर पूछा जाए, तो वह कहेगा कि आज इस महंगाई के लिए यह केन्द्र सरकार उत्तरदायी है, जो आम आदमी के मुद्दे को लेकर सरकार में आई थी। आम आदमी को कम दाम में चावल, कम दाम में दाल, कम दाम में तेल मिलेगा, आम आदमी को हर सुविधा मिलेगी, इस वायदे के साथ यह सरकार सत्ता में आ पाई है, लेकिन जब से ये सरकार में आए हैं, तब से ये अपने वायदे को भूल गए हैं। हमारे जो कृषि मंत्री हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि यह जो मूल्य वृद्धि हुई है, यह कब कम होगी, तो वे कहते हैं कि मैं astrologer नहीं हूं। जब वे कहते हैं कि कल से चीनी का दाम बढ़ेगा, तो चीनी के दाम बढ़ जाते हैं। वे केन्द्र के कृषि मंत्री हैं, कहां पर, किस राज्य में कितना कृषि उत्पादन होता है, यह जानना उनका दायित्व बनता है। अगर वे कहते हैं कि यह मेरा दायित्व नहीं है, तो वे इस दायित्व को छोड़ दें, कोई दूसरा व्यक्ति इसका दायित्व ले लेगा और इसे देखेगा। हिंदुस्तान के लगभग 100 करोड़ आदमी खेतिहर मज़दूर हैं। जो आम आदमी है, आज वह किस तरह से महंगाई से जूझ रहा है, अगर ये उसकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, तो उनको मंत्री पद पर रहने की कोई दरकार नहीं है, न ही इनको शासन में रहने की दरकार है। जब आम

* Expunged as ordered by the Chair.

आदमी के नाम पर वोट मांगकर ये सरकार में आए हैं और सरकार में रहकर अगर ये आम आदमी की तकलीफ को दूर नहीं कर सकेंगे, तो इनके सरकार में रहने का कोई औचित्य नहीं है। ये बोलते हैं कि हम astrologer नहीं हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इनसे astrologer बनने के लिए किसी ने नहीं कहा था। आपको यहां शासन करने के लिए भेजा गया था। आपको आम आदमी ने न तो astrologer के नाम पर शासन करने के लिए भेजा था और न ही आप कोई तांत्रिक बनकर यहां शासन करने के लिए आए थे। आप यहां पर प्रशासन बनने के लिए आए थे, हिंदुस्तान पर राज़ करने के लिए आए थे ...(**व्यवधान**)...

सुश्री मैबल रिबैलो : 11 सालों तक इनके मुख्य मंत्री ने क्या किया ...(**व्यवधान**)...

श्री किशोर कुमार मोहन्ती : मैं कृषि मंत्री जी से केवल इतना कहूंगा कि वे astrologer न बनें ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : मैबल जी, आप बैठिए ...(**व्यवधान**)...

श्री किशोर कुमार मोहन्ती : मैं कृषि मंत्री जी से केवल इतना कहूंगा कि वे astrologer न बनें, वे देश के प्रशासक बनें ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : मैबल जी, आप बैठिए ...(**व्यवधान**)... Ms. Mabel, please sit down. ***...(Interruptions)...*** Nothing will go on record.

सुश्री मैबल रिबैलो: *

श्री किशोर कुमार मोहन्ती : देश के किस प्रांत में कितने irrigation projects हैं, कितनी जमीन पर irrigation के लिए पानी मुहैया कराया जाता है, इस चीज को वे देखें ...(**व्यवधान**)... चीनी कब महंगी होगी, इस astrology में वे न पड़ें। अगर वे कहते हैं कि कल चीनी महंगी होगी, तो चीनी महंगी हो जाती है। जब उनसे पूछा जाता है कि दाम कब कम होंगे, तो वे कहते हैं कि मैं astrologer नहीं हूं। हम लोग तो यह नहीं कहते हैं कि आप astrologer हैं। आप तो देश पर शासन करने के लिए आए हैं, आम आदमी की तकलीफ समझने के लिए आए हैं, तो आप आम आदमी की तकलीफ समझिए ...(**व्यवधान**)... इसी कारण से महंगाई कम नहीं हो रही है। एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि जब-जब कांग्रेस सरकार आती है, तब-तब महंगाई बढ़ती है, जब-जब non-Congress Government आती है, तब-तब महंगाई कम होती है। पूरा इतिहास ही इस बात पर रखा हुआ है। उपसभापति महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। इसमें कह रहे थे कि हमारे देश में production बहुत कम हुआ है। आज का Economic Survey of India यह कहता है कि इसमें shortfall मात्र 9 प्रतिशत हुआ है, 9 से 10 प्रतिशत के बीच हुआ है और जो price rate है, वह कहीं 65 परसेंट, कहीं 100 परसेंट और कहीं 150 परसेंट तक बढ़ा है। यह बहुत दुख की बात है। वह इस बात को आज न समझें। वह ** बने रहें। आज वह ** हैं, उनको सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन जब ** का राज जाएगा, उस समय इनको समझ में आएगा कि आज जो गलत काम को प्रश्रय दे रहे हैं, उसके कारण इनको सत्ता से जाना पड़ा। धन्यवाद।

श्री राजनीति प्रसाद : सर, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझको बोलने का मौका दिया और उसके पहले श्री एस.एस. अहलुवालिया जी, जो यहां बैठे हुए हैं, को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि 167 से 176 पर आ गए। अगर 167 prevail करता, वहां भी लोक सभा में भी prevail करता, तो मेरे ख्याल से आज जो महंगाई एक burning issue है ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : इसमें भी सरकार ने नंबर कम नहीं किया है, बल्कि इसको 167 से 176 कर दिया है। इसमें भी उन्होंने कम नहीं किया है ...(**व्यवधान**)... उसमें भी ऊपर किया।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री राजनीति प्रसाद : सर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह डिबेट होती और जैसा कि Opposition Party ने adjournment motion लाया था, तो पूरे देश में जो महंगाई का स्तर है, अगर उस पर prevail करता, तो हमको लगता कि 99 की स्थिति आ जाती, क्योंकि यहां के बाद हम सारे लोग एक साथ थे और जो सरकार कमरतोड़ महंगाई लाई है, वह सरकार चली जाती। यह कांग्रेस की सरकार चली जाती। हम लोगों का यह दुर्भाग्य है कि जब-जब कांग्रेस की सरकार आई है, तब-तब पता नहीं इस देश में क्यों इतनी महंगाई आई है ...(**व्यवधान**)...

सुश्री मैबल रिबैलो : राजनीति जी ...(**व्यवधान**)... राजनीति जी ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : रिबैलो जी, कृपया आप उनको बोलने दीजिए। कृपया आप बैठिए। उनको जो बोलना है, उनको आप बोलने दीजिए। आपको जो बोलना है, आप बाद में बोलिएगा।

श्री राजनीति प्रसाद : सर, हम लोग बचपन से नारा लगा रहे हैं कि

"महंगाई जो रोक नहीं सके, वह सरकार निकम्मी है,

और जो सरकार निकम्मी है, वह सरकार बदलनी है।"

यह नारा हम लोग बचपन से लगा रहे हैं ...(**व्यवधान**)... हम लोगों ने, आरजेडी ने, लालू प्रसाद जी हमारे नेता हैं, 28 तारीख को महंगाई के कारण बिहार बंद किया था। पूरे हिन्दुस्तान में सिर्फ एक जगह महंगाई के कारण बंद किया गया, वह भी बिहार में किया गया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसा unprecedented बंद हम लोगों ने अपने जीवन में नहीं देखा है। 60 वर्ष के उम्र में हम लोगों ने नहीं देखा है। इसलिए नहीं देखा कि यह बंद पार्टी के लाइन पर नहीं था। यह आम जनता की बात थी और आम जनता ने हम लोगों को साथ दिया। सभी लोगों ने साथ दिया। सीपीआई के लोगों ने साथ दिया, सीपीएम के लोगों ने साथ दिया और तो और जो हमारे बीजेपी के लोग थे, वे लोग भी सड़क पर आकर बोले कि "रोको महंगी, बांधो दाम और नहीं तो होगा चक्का जाम"। उन लोगों ने भी गली और मुहल्ले से निकलकर हम लोगों का बंद में साथ दिया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि बंद में कौन साथ दिया, सड़क पर जो जूता सीने वाला होता है, उन्होंने भी बंद कर दिया। उनसे पूछा गया कि क्यों बंद किया, तो उन्होंने कहा कि महंगाई बहुत है, इसलिए हम लोग इसको बंद कर रहे हैं। सर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महंगाई का स्तर इतना ज्यादा हो गया है कि आम जनता को, जो गरीब लोग हैं, हमारे अर्जुन सेनगुप्त जी यहां बैठे हुए हैं।

इन्होंने एक मोटी किताब लिखी है, उसके दाम बहुत हैं - नौ सौ रुपए, लेकिन इन्होंने मुझे फ्री में दी है। सर, इसमें इन्होंने लिखा है कि 78 परसेंट गरीब लोग हैं और unorganised लोग हैं। जो बीस रुपया रोज़ कमाने वाले लोग हैं, उनके लिए गरीबी है, तो उनके लिए चीनी और तेल का क्या होगा। कड़वा तेल तो गायब ही हो गया है। हम लोग मुहावरा देते हैं कि गरीबों के लिए चीनी चरणामृत हो गया है और तेल इत्र हो गया है। जो आदमी बीस रुपया रोज कमाता है, उसको चीनी मिलना मुश्किल है। हमारे शरद पवार जी यहां कहते हैं कि चीनी खाने से डायबिटीज़ होती है, इसलिए चीनी मत खाओ, लेकिन सर, जो गरीब महिलाएं होती हैं, वह कुपोषण की शिकार होती हैं और उनको जब दूध नहीं होता है, तो उनके एक-डेढ़ वर्ष के जो बच्चे होते हैं, वे क्या नमक डालकर दूध पिएंगे? क्या गाय का दूध पिएंगे? क्या पिएंगे? इसलिए शरद पवार जी ने जो कहा है, वह हिंदुस्तान के गरीबों के साथ मज़ाक किया है। ...(**व्यवधान**)... गरीबों के लिए मज़ाक किया है और कहा है कि चीनी मत खाओ, लेकिन जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चे जो दूध में चीनी डालकर पीते हैं, वे कैसे पिएंगे?

सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)... आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए। सर, कड़वा तेल ...(**समय की घंटी**)... सर, घंटी मत बजाइए। कड़वा तेल इत्र की तरह हो गया है। हमें याद है कि बचपन में मां-बाप हमें कड़वा तेल लगाते थे कि बच्चे की हड्डी मजबूत होगी, बच्चे की सेहत ठीक होगी, लेकिन अब गरीबों को कड़वा तेल नहीं मिलता है, वह खत्म हो गया है। कड़वा तेल खत्म, चीनी खत्म, सब खत्म, तो कैसे होगा? सर, मैं कहना चाहता हूं कि यह इसलिए हुआ कि इस देश में बहुत सारी स्थितियां आ गई हैं और उन स्थितियों को बदलना पड़ेगा। पहला है कि हम यह चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि 'stop forward trading' यानी फ्यूचर ट्रेडिंग जो है, उसको हम लोग बंद करेंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग को बंद करेंगे, फिर हमारा मामला कुछ निकलेगा और ये जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो अपने यहां अनाज को बंद करके रखे हुए हैं, वह खुलेगा।

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं, आपसे भी कहना चाहता हूं कि डीहोर्डिंग के लिए ...(**समय की घंटी**)... एक मिनट... डीहोर्डिंग के लिए आपको एक नीतिगत निर्णय करना पड़ेगा। आप यह मत कीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट और फलां गवर्नमेंट... आपको डीहोर्डिंग के लिए एक नीतिगत निर्णय करना पड़ेगा, कड़ी punishment का प्रोविज़न बनाना पड़ेगा और पूरे मुल्क में डीहोर्डिंग करनी पड़ेगी। सर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।

श्री उपसभापति : उदाहरण देने के लिए समय नहीं है।

श्री राजनीति प्रसाद : सर, मैंने समय लिया है, मेरी बात सुनिए। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। बिहार में नीतीश जी की सरकार है। वहां पर डीहोर्डिंग की जरूरत है, लेकिन वहां डीहोर्डिंग नहीं हो रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विदेशी कंपनियों को रोज़गार के लिए यहां कोई साधन नहीं जुटाना चाहिए, कोई लोन नहीं देना चाहिए। किसी भी खाद्य वस्तु की खरीद के लिए उनको नहीं देना चाहिए ...(**समय की घंटी**)... मैं कहना चाहता हूं कि जो विदेशी पैसे यहां आते हैं, वह बिना सूद के आते हैं, उन पर सूद नहीं लगता है, तो उनको...

श्री उपसभापति : श्री साबिर अली, बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजनीति प्रसाद : तो उनको यहां पर रोज़गार करने के लिए कोई मौका नहीं देना चाहिए। सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारी बातों को अगर हम करेंगे, तो हमें लगता है कि यहां पर महंगाई जरूर कम होगी और अगर महंगाई कम नहीं होगी, तो फिर यह सरकार...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I have called his name. देखिए, आप पहली मर्तबा ऐसा ...(**व्यवधान**)...

श्री राजनीति प्रसाद : सर, अंत में मैं दिनकर जी की पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। वह इस प्रकार है-

"समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध,

जो तटस्थ है, समय लिखेगा उसका भी अपराध।"

यह कांग्रेस पार्टी तटस्थता के भाव अपना रही है, उसका भी अपराध इतिहास में लिखा जाएगा, धन्यवाद।

श्री साबिर अली (बिहार) : सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बातों को शुरू करने से पहले एक शेर कहना चाहता हूं। मैंने विपक्ष को भी सुना, पक्ष को भी सुना, बीच वालों को भी सुना। इधर हाफ है, इधर पूरा साफ है। मैं एक शेर कहता हूं-

बड़ी मुश्किल है पहचानूं, मोहब्बत किसकी सच्ची है।

न तेरी आह सच्ची है, न तेरी राह सच्ची है।

Sir, before I begin. ...*(Interruptions)*... आप तो * हैं यह मैं जानता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : * शब्द नहीं जाएगा।

SHRI SABIR ALI: I am sorry, Sir, I take back my words. सर, कल 24 तारीख की टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आपके पास पांच मिनट हैं और उसी में आपको खत्म करना है।

श्री साबिर अली : सर, मेरे पास बहुत ज्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है। सब लोगों ने बोल दिया है। सब लोग देख सकते हैं कि महंगाई इतना बर्निंग ईशू है लेकिन पूरा हाउस इस वक्त प्रेज़ेंट नहीं है। आपके कैबिनेट के एक सिंगल मंत्री हैं। जो सदन में पांच लोग होने चाहिए, वे लोग भी पूरे नहीं हैं। आपके लॉ बुक्स को देख लिया जाए। जहां तक मेरी जानकारी है, आपके पांच मंत्री भी नहीं हैं, लॉ बुक के हिसाब से वे भी यहां पर प्रेज़ेंट नहीं हैं। यह बड़ी अफसोस की बात है कि इतने बर्निंग ईशू पर लोग इस हाउस में प्रेज़ेंट नहीं रहते हैं। दो दिन सदन बाधित हो गया और जब हम सुनने और कहने ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आपने क्या कहा है? ...(**व्यवधान**)... इधर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री साबिर अली : मैं वही बोल रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : साबिर अली साहब, आप मुझे देखकर बात करिए। You address me. कैबिनेट मिनिस्टर हाउस में हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री साबिर अली : सर, पांच नहीं हैं। कम से कम पांच होने चाहिए।

श्री उपसभापति : यह रूल कहीं नहीं है, आप खुद अपना रूल बना रहे हैं। आप सब्जेक्ट पर आइए।

प्रो. अलका क्षत्रिय : पहले आप जानकारी पूरी लीजिए।

श्री साबिर अली : आप सुनिए। आपसे ज्यादा जानकारी है। आपसे ज्यादा किताब पढ़कर आया हूं। ...(**व्यवधान**)... मैं आपके भाषण सुनता हूं ...(**व्यवधान**)... आपसे सुनने की जरूरत नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आपको उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री साबिर अली : सर, यह चार क्वॉटर की रिपोर्ट है। हमने सत्ता पक्ष का सुना कि महंगाई दूर करने के लिए बहुत कोशिश चल रही है, दिर रात कोशिश चल रही है, मेनिफेस्टो बनाया जा रहा है, इनके यहां mechanism बनाया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार क्वॉटर-1 में 16 परसेंट, क्वॉटर-2 में 18 परसेंट, क्वॉटर-3 में 34 परसेंट पल्सेज़ की कीमतों में वृद्धि लगातार होती जा रही है। अभी जो लास्ट क्वॉटर की रिपोर्ट आई है, उसमें 48 परसेंट की वृद्धि की रिपोर्ट आई है। यह सरकारी रिपोर्ट है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम लोग महंगाई की बात करते हैं, सरकार का पूरा mechanism लगा हुआ है। अभी वित्त मंत्री साहब ने भाषण दिया। उन्होंने गेहूं का तर्क दे दिया कि गेहूं हमारे यहां महंगा क्यों मिल रहा है। उन्होंने चावल का तर्क दिया कि चावल कुटाई के बाद 67

---

* Expunged as ordered by the Chair.

परसेंट आता है, उसमें धान की भूसी निकल जाती है, फिर चावल बच जाता है। पल्सेज़ का तर्क उन्होंने नहीं दिया, तेल का नहीं दिया, मिर्च का नहीं दिया, मसालों का नहीं दिया। वे सब चीजें इस देश के लिए essential हैं। आप जब आते हैं, अपने पक्ष की बात करते हैं और महंगाई पर वह डाटा दे देते हैं जो रेलेवेंट नहीं होता है, जो सबको जानकारी है। आप उस डाटा से हट जाते हैं जो रेलेवेंट है, जिसमें आपकी कहीं-न-कहीं भागीदारी है, हिस्सेदारी है। सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि जो चीज़ किसानों से खरीदी जा रही है और जो यूज़र हैं, उनको किस दाम पर वह चीज़ मार्किट में बेची जा रही है, इसमें बहुत बड़ा गैप है। यह सरकारी आंकड़े हैं। आज आपको मिसाल के तौर पर प्याज का आंकड़ा देना चाहता हूं। आज बाजार में जो प्याज बेचा जा रहा है, वह किसान से पांच रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है। जब वह मार्किट में जाता है तो उसकी कीमत 23 रुपए हो जाती है। बीच में 18 रुपए का गैप है। एक अदने से प्याज के दाम में गैप 18 रुपए है। यह किसकी वजह से है? अगर आप बात करते हैं कि इसमें प्रदेश सरकारों की बहुत बड़ी भागेदारी है तो मैं कहना चाहता हूं कि जितने आपके प्रदेश हैं, जहां कांग्रेस की हुकूमत है, वहां पर सबसे ज्यादा इसके बिचौलिए हैं। आपने वहां पर रोक क्यों नहीं लगाई? आप अपने प्रदेशों में क्या कर रहे हैं? यह सोची-समझी साजिश है और इसमें कहीं न कहीं हमारे बड़े लोगों की - जो इस देश में सत्ता पर बैठे हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, इनकी कहीं-न-कहीं इसमें मिली भगत है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जितने भी इससे कंसंर्ड डिपार्टमेंट हैं, उनकी इन्क्वायरी सही तरीके से होनी चाहिए। इसे कैसे कम किया जाए, इस संबंध में सही कदम उठाने की जरूरत है, आपको देश देख रहा है, आपको देश ने चुनकर भेजा है। आपको देश ने पहले हटाने का भी काम किया। अगर आप सिर्फ यही कहते रहे कि हम सत्ता में आते रहे हैं - यहां पर राशिद अल्वी जी ने कहा कि महंगाई आती है तो भी हम सत्ता में आते हैं - यह इनकी भूल है। आप कई बार सत्ता से गए हैं। अगर आपका यही मिजाज़ रहा, अगर आप ऐसा ही सोचते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब आप सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। यह देश की जनता जरूर मासूम है, लेकिन * नहीं है। आप मासूमों को ऐसा * नहीं बनाओ, इस देश की जनता * नहीं है। इसलिए अभी भी होश में आ जाओ और कम से कम ऐसा कदम उठाओ कि महंगाई पर जो गरीबों का, मजदूरों का पेट जल रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, उससे कम से कम वे निजात पाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का।

SHRI BHARATKUMAR RAUT (Maharashtra): Sir, I know that I am too late now to speak. Most of the points which I wanted to make have already been made. It also shows the commitment of the ruling party towards the issue of price rise when 14 Members of the ruling side are sitting in the House when discussion is going on. ...*(Interruptions)*...

श्री शान्ताराम लक्ष्मण नायक (गोवा) : चौदह ही चार सौ के बराबर है। ...*(Interruptions)*... *

SHRI BHARATKUMAR RAUT: Anyway, I don't want to make a mockery of the issue. As I rise here, my head hangs in shame and my heart bleeds. When we are discussing this issue of price rise, 33 crore Indians outside this august House those, who are surviving below the poverty line, are left to the mercy of the God. They are surviving, only waiting for death. They have no optimism or hope left in this country and in this Government. It is an utter shame that in this situation, instead of making serious efforts to ease the plight of the hungry population, our Government and the ruling alliance is busy in giving figures by which neither they are convinced nor can they satisfy the hunger pangs of the people.

Sir, it is often claimed that the price rise in India is due to the failure of monsoon and the global meltdown. It is a shameless attempt to misguide the people to cover up the corruption, political

* Expunged as ordered by the Chair.

selfishness and bureaucratic inefficiency. Yes, there is a global meltdown for the last couple of years. There is no denial about it. But, is the price rise of essential commodities, foodgrains, etc. in India due to the meltdown? Just check it up. You all will agree that the USA is the worst hit due to the meltdown crisis. The banks there are collapsing and monetary system is facing the fury. However, the prices of the essential commodities like milk products, foodgrains, bread, etc. are not affected the way they have affected in India. This has happened because the Government in the USA, at various levels, have taken care to see that the prices of essential commodities are kept under control and are not adversely affected. That political will is lacking in India and that is the problem.

Now, let us think about the failure of *kharif*. This is not the first time that *kharif* failed. Our Leader of Opposition has mentioned that in 2002, when the nation was ruled by the NDA, the situation was worse. The shortfall of foodgrains was four times more than in 2009. However, the food inflation was controlled to three per cent. This could happen because the Government had the will and control over the bureaucracy. Here, let me mention that when the Shiv Sena-BJP Government was in power in Maharashtra from 1995 to 1999, the prices of five essential commodities – rice, wheat, edible oils, sugar and kerosene – remained same for all the four-and-a-half years. We had put up a hoarding in front of the *Mantralaya* that these will be the prices ...*(Interruptions)*... Let me complete Mr. Naik. We saw to it that despite all problems, the prices were controlled and remained where they were. I mean, this needs a political will. This needs the control to ride over the bureaucracy. This is not happening here because this Government, though it is elected by the people, is run by * It is run by those who are*.

And the Government is falling prey to their wishes. Let me recall that 17 States in this country withdrew as many as 1.5 crore BPL ration cards as they were found to be fake. In Maharashtra, I am told that 29,45,000 such bogus ration cards were found. Of these, over 25 lakh card-holders were Bangladesis. Who are responsible for this? Out of 29 lakh cards, 25 lakh cards belong to the illegal immigrants from Bangladesh. Who are responsible? Who issued those cards? Why should illegal immigrants from Bangladesh be allowed to take advantage of our schemes meant for our poor people? Nobody is bothered about it. It is because of the fact that this is a vote bank politics. That is why you have no guts to see that those ration cards are removed. They are removed, they are withdrawn only after the Lok Sabha and the Assembly elections. This is politics. I think, the nation needs an answer as to who is responsible and what action the Government has taken.

Sir, there are no serious efforts from the Government either in the Centre or in the Congress-ruled States, like Maharashtra, to curb rising prices and bring in relief to the people. The hon. Prime Minister is a noted economist. I wish to ask him one question. How do you justify the fact that on the

* Expunged as ordered by the Chair.

one hand, the prices of rice, wheat, sugar, of all these essential commodities are going up every day? They are hitting the roof. On the other hand, the prices of cosmetics, luxury items, TV sets, mobile phones, DVD players are coming down sharply. When the prices of the essential commodities are going up, the prices of the luxury items are coming down. What type of economy is this? What is the wisdom in this? Whom are you are running the Government for? Who is the beneficiary of your politics? Who is the beneficiary of your policies? ...(**Time Bell rings**)...

Sir, I will take another two minutes. Sir, on the one hand, a CEO of a company in India draws a huge remuneration of over Rs. 24 crore for his six-member family annually. On the other hand, 33 crore people do not get even 20 rupees per day for their survival. We are talking of socialism. On the one hand, there is a remuneration of Rs. 24 crore per annum for one person; on the other hand, 33 crore people are surviving on 20 rupees per day. Where is the parity? What are we talking about?

Sir, I do not see the end of price rise in the near future. Now, the Government wants to de-control non-urea fertilizers. What is the logic, rationale or wisdom in this? This would add to the plight of small and marginal farmers. If they stop producing foodgrains, we will have to increase the foodgrains import, and the import bill will be many times bigger than the Rs. 40,000 crore that you intend to save by the new subsidy policy.

As an immediate step to provide some relief to the middle income and the poor people, we must improve the PDS. That is the crux of the whole problem. That is the root cause of the whole problem. The experience of the consumers is that the foodgrains allotted to the PDS find way to the private shop-owners. This happens because of the nexus between the PDS employees and shop owners. Break their ties immediately and then you will find the result. Let the PDS quota go to the poor at the control price. To do this, you need courage and a will which is lacking. The Government must rise to the call of the people today because tomorrow will be too late.

Sir, without going into more details and arguments, my only submission is that leaving behind the game of figures and one-upmanship, let us get back to work and save the common man. We have been witnessing suicides of the farmers for the last five years.

If the price-rise continues like this, I am afraid there would be cases of suicide by consumers and housewives. Let us avert this situation for God's sake. Thank you, Sir, for giving me time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Mr. Raut. Now, Shri Arjun Kumar Sengupta.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA (West Bengal): Thank you very much, Mr, Deputy Chairman, I understand, I am the last speaker. It is a matter of great pride for me because I came

prepared to respond to the criticisms of all the speakers, sentence by sentence, ...*(Interruptions)*...

PROF. P. J. KURIEN (Kerala): It is a privilege to be last speaker.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: Well. I mean, please listen to me and then report to Mr. Sharad Pawar. I am mentioning this, because the only reason I got up is that despite having all my earlier plan to rebut the speeches made by the Opposition Members, sentence by sentence, I shall not proceed further on that as I have very little time as a last speaker. But I do want to say a few things which, I hope, will be reported back to Mr. Pawar so that he replies. I suspect he will not do that, but I want to be on record that these suggestions I am making should be reported when answers are given. Mr. Kurien, particularly, you, may do so as I do not find anybody else responsible. ...*(Interruptions)*...

PROF. P. J. KURIEN: Every speech will be reported here.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: But there is a particular point I am making.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister is there.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: Okay. Very good. I hope that he answers this question.

Now, let me come to the basic point. I have been listening to these discussions. There is a huge confusion here between long-term factors or causes of price increase and short-term causes of price increase. The Government of India, particularly this Government, has taken many, very appropriate, policies for increasing the long-term supply, not only of foodgrains but also of agricultural products. This may be debated; this may be discussed, but I don't think any other Government has done as much as this Government has done for the long-term development of the country, which, in one form, has been reflected in the high rate of growth but which, in another form, in which the plans are being made, will also be reflected, particularly, in the foodgrain products. But this is a long-term solution. In fact, I will just mention one thing. Mr. Arun Jaitleyji, in his speech, mentions about the minimum support price. This has come back again and again. He says that the minimum support price should not be taken as an alibi for price increase because it will increase the income of the farmers, and, as a result of which, the farmers will increase their output. This is, again, a long-term solution. Immediately, when you increase the minimum support price, it increases the price that you pay and, therefore, the price that you charge. So, there will be an effect on the price increase, an immediate effect; in long term, of course, it will neutralise. Now, I am not going to say anything about whether that price increase is justified or not. The technical experts of the Government say they are not. In fact, the Agricultural Prices Commission categorically says that these increases in prices are not justified by the increase of cost and all that. But that is not the

subject under debate today. All I am saying is that in the short run, the rise in prices, procurement prices, will be reflected in the price increase of the commodities, but, in the long run, it will definitely neutralise itself. I can go on on this question, again and again, the question of fertiliser subsidy, the prices, the petroleum prices; all of these are very effective things. It will take care of the problem over a period of time. In fact, the latest change in the fertiliser subsidy policy will increase the productivity of fertilisers in our country and will also increase the productivity of agriculture and foodgrains, but, again, not immediately, but over a period of time. So, we must make a distinction between these two aspects. In the short run, immediately, there is no doubt that prices have increased very substantially, prices of not all commodities, but, of foodgrains, and prices of essential commodities/products. Everybody admits it. The statistics are quite well known. What are you going to do with them? Now, I submit to you, as I consider myself – I am a Congressman for a long time – nobody can ignore this price rise; the BJP may ignore it.

I don't think the Left Parties can ignore it. But others may ignore it. But the Congress Party can't ignore the fact that this is the worst possible hit that it is making to the *aam admi*. There is a report that has been published. It is reported again and again that the per capita consumption is Rs.20. Don't bother about anything else, poverty line, etc. But the statistics is true. Seventy-seven per cent of our population is consuming less than Rs.20 per day in 2004-05. That might have come down to 75 per cent. I am not saying the same situation is there today. The situation is improving. Out of Rs.20, you just exhaust most of it on just foodgrains.

PROF. P. J. KURIEN: Fifty-seven crores of our people have mobile phones. That is the latest report which I have seen. I want to know, if your argument is correct ...*(Interruptions)*...

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: No. I am aware of this. I am aware of your point. Our cell phone sales have increased. ...*(Interruptions)*...

PROF. P. J. KURIEN: A person who has got Rs.20 per day can never have a telephone. ...*(Interruptions)*... He can never have a telephone.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: I am not manufacturing the statistics. I want to point it out very clear, Prof. Kurien. You are an academic.

PROF. P. J. KURIEN: I don't want to score any point. It is only for academic interest.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: No, no. It is not scoring a point. What I am saying is that it has come back again and again here. I am telling you that this statistics is not manufactured by me or by my group. It has been given to us by the National Sample Survey done by the country's most important Statistical Organisation. It is famous not only in India but also all over the world. All over the

world the Indian statistical exercise is considered to be an example. Prof. Mahalonobis was the father of this survey method. So, don't charge this question. I am giving you the numbers given by the Organisation. These are the numbers that the NSS has given. It gives 77 per cent. I can consider it 75 per cent. If you wish, 72 per cent of the people are now having Rs.20. They can't afford anything else. ...*(Interruptions)*... Ahluwaliaji, are you saying something?

SHRI S. S. AHLUWALIA: You are quoting from your own report. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: I am not quoting. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. S. AHLUWALIA: You have made the report. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: I am only replying to Prof. Kurien's point. This is not my report. This is a, report by the Statistical Organisation. We can't afford to ignore the effect of price rise on these people. Our party has come to power on the basis of a slogan or platform, "We are different from the NDA; we are different from the BJP; we are not that party which talks about India shining; we are for the common man, the people who suffer". ...*(Interruptions)*...

SHRI S. S. AHLUWALIA: Are you?

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: I do. Yes, of course. The whole Congress Party, all these people around the country have got the votes. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. S. AHLUWALIA: What Mr. Kamal Nath has said is that because the purchasing power of the people has increased, the people are eating more and that is why there is price increase. Do you agree with that?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ahluwalia, let him complete. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. S. AHLUWALIA: You were saying that the purchasing power of the common man was like this. It was so much percentage. Now, you say that it is not your programme. It is self-contradictory.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: Mr. Ahluwalia, there is no contradiction in this. What I am saying is that the Congress Party which has come to power on this slogan can't ignore it. They must do something to protect the common people. In other words, even if I can't do much about price increase, as a matter of fact, in the entire discussion it has become very clear that in the short run you can't stop the price increase. Then, what you have to do is to protect some section of the people and for the Congress Party, for this Government, the mantra has to be, "We must protect the vulnerable group, which is the aam admi, who are the poorest of the poor". How do you do that?

This is the point I want to be reported to Mr. Sharad Pawar. He should be able to answer that. There is no other way of protecting them except universalisation of Public Distribution System. My friend, Shrimati Brinda Karat, had raised this issue and some others had also raised this issue. There is no other way by which these people can be protected. The question is: What is the Government doing? Now, in the case of Public Distribution System, three things are necessary. We have to have adequate supply of grains. If you are unable to get it from the domestic procurement ...*(Interruptions)*...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : यह तो फाइनांस मिनिस्टर के खिलाफ बोल रहे हैं।

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: I am not speaking against anybody. They all listen to me. I am just putting forward...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: At the last minute, I am saying this because I want this thing to be answered. But I am afraid it will not be answered. The point is that we have to increase the supply of grains. How will you do that? If there is a shortfall in production, the only way to do this thing is by imports or your Food Corporation of India entering into the domestic market, procuring at the domestic market price and then selling it at a cheap price through the Public Distribution System. What does that mean? It means an immediate increase in subsidies. It means an immediate increase in the Government expenditure. If your revenues are not increasing, you are faced with a choice. Do you accept this? The result of which may be an increase in deficit. Or you do not! Because an increase in deficit has definitely certain implications for pure capitalist development because they would like to have a rate of return which will justify their investment and that may have an effect on the rate of growth. So you have a choice. Are you going to do this? Because it may have an effect on the growth. You have to do this.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal): Shri Sharad Pawar has rejected this.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: In fact, I am raising this issue because I heard Pranab Babu. Pranab Babu also said how would he do it. Now this is a choice before you. If you can do this by reducing expenditure elsewhere, whether it is in armaments whether it is in police force – whenever I say in police force, they will say Naxals is a big problem - whichever way you can do it, do the change in cost of administration. You have to reduce expenditure unless you can increase revenue. You can also increase revenue. Tomorrow there will be a Budget. Don't give these concessions on excise duty, etc. You can have many different ways of doing it. But if you cannot, then there will be an increase in deficit. As a result of that, it may have an effect on growth. The choice before you is whether you would accept that possibility, the risk of that and look for something for the common people. Sir, my main point is: Is Shri Sharad Pawar or the Government thinking of a standing mechanism of Public Distribution System to be universalised, not necessarily, to begin with, to everybody, to the poorest of the poor, to the BPL people? ...*(Interruptions)*... One can do the calculation. It is not very difficult. Do protect them. In order to protect them, what steps are you

going to take? This question of the Public Distribution System has been raised here again and again and again. We have talked about imports. Unfortunately, we enter the import market when the prices are very high. If we have a standing mechanism, you will play the market. If our Food Corporation of India were dealing in grains marketing, it would know when to buy and when to sell. We have to build up an organisation, a particular mechanism so that this is a permanent feature in a system where the main objective of the system is to protect the poor and the vulnerable. This is my point. I would like this thing to be answered by Shri Sharad Pawar that yes, we are thinking in terms of doing that and then come back to us. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, the debate on the Short Duration Discussion is concluded. The reply to the debate will be on 3rd March, 2010.

RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform the Members that the Business Advisory Committee in its meeting held on the 25th February, 2010, has allotted time for the Government Legislative and Other Business as follows:-

Business	**Time Alloted**
Consideration and return of the Railway Appropriation Bill relating to the following Demands for Grants, after they are passed By Lok Sabha:-	
(a) Demands for Grants on Account (Railways) for 2010-11	
(b) Supplementary Demands for Grants (Railways) for 2009-10.	Two-and-a-half hours (To be discussed together)
(c) Demands for Excess Grants (Railways) for 2007-08.	

The Committee recommended that there would be no sitting of the House on Tuesday, 2nd of March, 2010.

The Committee also recommended that the House may sit up to 6 p.m. and beyond, as and when necessary, for the transaction of the Government Legislative and Other Business.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 1.30 p.m. on Friday, the 26th February, 2010.

The House then adjourned at thirty minute past six of the clock till thirty minutes past one of the clock on Friday, the 26th February, 2010.